नई सोच • नई शुरूआत • नया भारत

अनप्लग इंडिया

सच की आवाज, भारत की पहचान

नोएडा एनसीआर संस्करण

वर्ष : 01 | अंक : 57 | नोएडा, शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2026 | Website: www.unplugindia.com | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 03 रुपए

आज का विचार

हर नया दिन एक नया अवसर है, इसे अपने सबसे अच्छे तरीके से जिएं।



सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

पैकेट पर अब लगानी होगी चीनी, नमक और फैट की चेतावनी



नई दिल्ली, एजेंसी। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में मौजूद हानिकारक तत्वों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने खाने-पीने की पैकेट वाली चीजों पर वॉर्निंग लेबल लगाने को कहा है। ताकि उपभोक्ताओं को यह पता चल सके कि वह जिस चीज का सेवन कर रहे हैं, उसका उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से कहा है कि फ्रंट-ऑफ-पैकेज न्यूट्रिशन लेबलिंग नियमों को सख्त किया जाए।

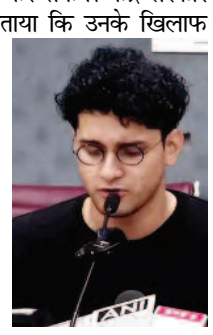
कोर्ट ने दिए ये निर्देश....

कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि पैकेट के अगले हिस्से पर 'एडेड शुगर' और 'एडेड फैट' के बजाय 'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' को नमक के साथ चिंताजनक पोषक तत्वों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। हर निशान छह कोनों वाला होगा। उसमें संबंधित चीज की तस्वीर के साथ उसके बगल में 'हाई फैट', 'हाई शुगर' या 'हाई सॉल्ट' जैसे शब्द लिखने के निर्देश दिए गए हैं। यह उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ खरीदते समय सही फैसला लेने और स्वस्थ खान-पान के विकल्प चुनने में मदद कर सकता है। पीठ ने आगे कहा, 'एफएसएसएआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि FoPNL में 'एडेड शुगर' और 'एडेड फैट' के बजाय 'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' को 'नमक' के साथ-साथ मुख्य चिंता वाले पोषक तत्वों के रूप में माना जाए।

सीजेपी नेता सौरव दास के खिलाफ लुकआउट नोटिस

सरकार बोली- पासपोर्ट पर पिता के नाम का कॉलम खाली, जन्मस्थान और पते में भी फर्क

नई दिल्ली, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास फिलहाल विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। सरकार के मुताबिक, उनके पासपोर्ट में पिता के नाम का कॉलम खाली है। इसके अलावा जन्मस्थान, पढ़ाई और पते से जुड़ी जानकारियों में भी अंतर मिला है। सरकार ने कहा कि इन गड़बड़ियों का असर उनकी नागरिकता पर भी पड़ सकता है। दरअसल, 23 नवंबर को सौरव को दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया था। उन्हें ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में 'कॉकरोच मूवमेंट' पर बोलना था। इसके बाद 24 नवंबर को सौरव दास ने विदेश जाने से रोके जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान केंद्र ने बताया कि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है।



कीमत करीब 208 करोड़, यह किसी भक्त का अब तक का सबसे बड़ा दान

तिरुपति में दंपती ने चढ़ाया 121 किलो सोना

चेन्नई, एजेंसी। तिरुमला के तिरुपति मंदिर में चेन्नई के एक भक्त ने गुरुवार को 121 किलो सोने के आभूषण दान किए। इनकी कीमत करीब 208 करोड़ रुपए है। यह दान वर्धमान जैन और उनकी पत्नी राधिका जैन ने दिया है। यह दान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में हुआ।

इस दान में 9 सेट में रखे 45 जेवर और 238.2 कैरेट के हीरे शामिल हैं। इनमें श्रीवारु (भगवान वेंकटेश) का मुकुट और पद्म पादालु यानी पैरों के आभूषण भी शामिल हैं। तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर को किसी एक भक्त की ओर से दिया गया यह अब तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है।

कंपनी में अपना हिस्सा बेचा, उसी से जेवर बनवाए

चेन्नई की कंपनी 'वारा फ्यूचर एलएलपी' के चेयरमैन वर्धमान जैन ने 121 किलो सोना दान किया। वर्धमान ने कंपनी में अपनी 60% हिस्सेदारी बेचकर 6000 करोड़ रुपए हासिल किए थे। इसी रकम में से वर्धमान ने भगवान श्री वेंकटेश्वर को यह सोना दान किया।

पहले भी कई बार दान को लेकर चर्चा में रहे

2024: चेन्नई में एक मंदिर के विस्तार के लिए 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया।



नवंबर 2024: टीटीडी के 'अन्न प्रसादम ट्रस्ट' को 1.01 करोड़ रुपए और 'प्रणदानम ट्रस्ट' को 1.01 करोड़ रुपए दान किए।

2025: एसवी भक्ति चैनल को 5 करोड़ रुपए और गौ-संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए।

मई 2026: तिरुपति के लिए एक इलेक्ट्रिक बस दान करने की घोषणा की।

अपनों ने ठुकराया, किस्मत ने मिलाया... हिमाचल के वृद्धाश्रम में हुई दिल को छू लेने वाली शादी

गुफा में जिंदगी गुजारने वाले 75 के कन्हैया को मिली 63 साल की सबीना

बिलासपुर, (हिमाचल प्रदेश) एजेंसी। हिमाचल प्रदेश में 75 साल के दूल्हे ने 63 साल की दुल्हन से शादी रचाई। दूल्हा हिमाचल के मंडी के रहने वाले हैं, जो पत्नी की मौत के बाद इस कदर टूटे कि जंगल में गुफा में रहने लगे। हालत बिगड़ी तो एक संस्था उन्हें वृद्धाश्रम में ले आई। इसी बीच पति की मौत के बाद मानसिक हालत बिगड़ने पर पश्चिम बंगाल की सबीना भी ट्रेन पकड़कर शिमला पहुंच गई। उन्हें भी संस्था ने अपने वृद्धाश्रम में रख लिया। जहां दोनों की मुलाकात हुई और अब उन्होंने शादी कर ली। दोनों अब पति-पत्नी के रूप में नए वृद्धाश्रम में रहेंगे। यह संभव हुआ हिमाचल की मानव सेवा संस्था के संस्थापक एवं चेयरमैन प्रकाश बंसल के सहयोग से, जिन्होंने पूरे रीति-रिवाज से दोनों की शादी कराई।

पत्नी की मौत के बाद घर छोड़ जंगल में रहने लगे कन्हैया- मानव सेवा संस्था के संस्थापक एवं चेयरमैन प्रकाश बंसल ने बताया कि मंडी के रहने वाले कन्हैया लाल की पत्नी की साल 2021 में मौत हो गई। इस सदमे से वह इतने टूट गए कि घर-परिवार छोड़कर जंगल में रहने लगे। करीब 7 महीने गुफा में बिताए। 2022 में ट्रस्ट ने रेस्क्यू किया। उस दौरान उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई थी और वह जिंदगी से निराश हो चुके थे।



पहले अस्पताल पहुंचाया, फिर वृद्धाश्रम लाए- मानव सेवा ट्रस्ट की टीम को कन्हैया के गुफा में रहने की जानकारी मिली। टीम ने उन्हें वहां से रेस्क्यू किया और अस्पताल में उपचार करवाया। इसके बाद उन्हें बिलासपुर के 'अपना घर' वृद्धाश्रम लाया गया। यहां रहने, देखभाल और उपचार की सुविधा मिली। धीरे-धीरे उनकी स्थिति में सुधार होने लगा और वह सामान्य दिनचर्या में लौटने लगे।

सपा का चुनावी घोषणापत्र

युवाओं को 5000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता, वृद्ध महिलाओं को 40 हजार सालाना

लखनऊ, एजेंसी। *समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को घोषणा-पत्र जारी किया। इसमें युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने, वृद्ध महिलाओं को सालाना 40 हजार और 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को टीचर्स के बराबर वेतन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा, गरीब परिवारों को 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देने, बंद स्कूलों को फिर से खोलने और पुरानी पेंशन बहाल करने की दिशा में काम करने का वादा किया। अखिलेश ने कहा कि आशा, आंगनबाड़ी और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को अच्छा वेतन दिया जाएगा। उन्हें नौकरी में पक्का करने के लिए भी काम करेंगे।*

साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान दिवस पर भाजपा और संविधान बदलने की बात करने वाली शक्तियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और संविधान को बदलने की साजिश कर रहे हैं। ऐसी कोशिशों को नाकाम करने के लिए सभी संविधान समर्थक एकजुट हैं। अखिलेश ने कहा कि कुछ प्रभुत्ववादी और स्वार्थी लोग अपनी परंपरागत सत्ता बनाए रखने के लिए संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। समीक्षा और पुनर्विचार के नाम पर संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऐसी शक्तियों को संविधान विरोधी, संकीर्ण सोच वाला और विध्वंसकारी बताया। 'हमारा देश संविधान से चलेगा, मन-विधान से नहीं।' अखिलेश के मुताबिक, संविधान शोषित और वंचित वर्गों के लिए ढाल की तरह है। सभी संविधान प्रेमियों का कर्तव्य है कि वे एकजुट होकर संविधान के खिलाफ किसी भी साजिश को सफल न होने दें।



सपा के साथ सीट बंटवारे के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इमरान मसूद को दी नसीहत

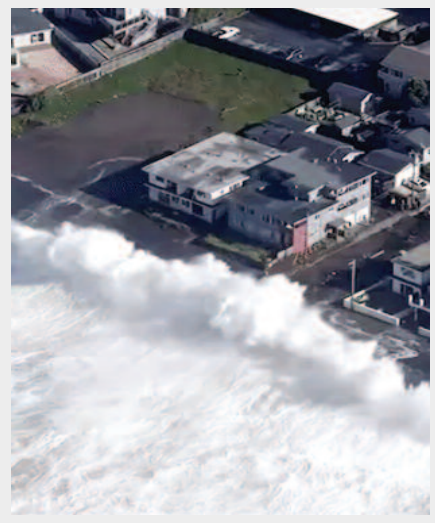
बीजेपी सरकार पर भी बोला हमला

लखनऊ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। लगातार दूसरे दिन यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद सपा पर आक्रामक नजर आए। सपा के 26 सीट ऑफर करने से इमरान मसूद इतने खफा हैं कि उन्होंने आज भी कहा कि हम सपा के पार्टनर हैं या नौकर। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इमरान मसूद को नसीहत दी है। उन्होंने मसूद को कम बोलने की सलाह दी। खरगे ने कहा कि हमे बोलने से ज्यादा काम करना है। संविधान दिवस के मौके पर लखनऊ में खरगे ने कहा कि कांग्रेस ने ही बाबा साहेब को संविधान सभा में पहुंचाया और उन्हें ड्राफ्टिंग कमिटी (प्रारूप समिति) का अध्यक्ष बनाया। संविधान सभा में बाबा साहेब अंबेडकर का होना बहुत जरूरी था क्योंकि उनके बिना देश का संविधान ठीक से नहीं बन सकता था। खरगे ने कहा कि आज दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक तरफ हम हैं जो संविधान के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ वे हैं जो इसका विरोध करते हैं। जो हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं। पिछले 12 सालों से, संविधान विरोधी सोच रखने वाले लोग लगातार संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं।

अमेरिका में तूफान से 6000 फ्लाइट्स लेट, 150 उड़ानें रद्द

ऊंची लहरों से बाढ़ का खतरा बढ़ा

वाशिंगटन। अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के बीच खराब मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पूर्वी और पश्चिमी तटों पर आए तूफान के कारण बुधवार को 6000 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुईं, जबकि करीब 150 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। सबसे ज्यादा असर पूर्वी तट पर देखने को मिल रहा है। यहां 'नॉरईस्टर' नाम का तूफान आगे बढ़ रहा है। इसके चलते न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया और आसपास के इलाकों में तेज



हवाएं और भारी बारिश होने की आशंका है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। कैलिफोर्निया समेत कई राज्यों में इससे निपटने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच मियामी एयरपोर्ट पर भारी बारिश के कारण एक मालवाहक विमान उतरते समय रनवे से आगे निकल गया। इसके बाद कुछ समय के लिए एयरपोर्ट के ज्यादातर रनवे बंद करने पड़े, जिससे विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई।

14 साल में सबसे ऊंचा जलस्तर होने का अनुमान

अमेरिका के पश्चिमी तट पर तेज लहरों के कारण समुद्र किनारे बने ढांचों को नुकसान पहुंचा है। सैन डिएगो के आसपास समुद्र का पानी पुराने रिकॉर्ड से भी ऊपर पहुंच गया। इससे आसपास के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका के पूर्वी तट पर 2012 में आए सुपरस्टॉर्म सैंडी के बाद अब समुद्र का जलस्तर सबसे ज्यादा हो सकता है। डेलावेयर और न्यू जर्सी के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के कारण बिजली गुल होने का भी खतरा है। देश के मध्य हिस्सों में बुधवार से शुक्रवार तक बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। वहीं, पैसिफिक नॉर्थवेस्ट इलाके में बुधवार रात से बारिश और तेज हवाओं का एक और दौर शुरू होने की आशंका है।

आईआरसीटीसी घोटाला मामला

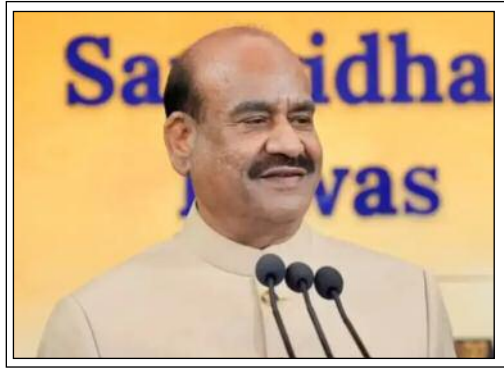
लालू परिवार को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

नई दिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ट्रायल कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को सभी के खिलाफ आरोप तय किए थे और कहा था कि प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकलता है कि लालू यादव को पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी और उन्होंने होटलों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप किया।

टेंडर प्रक्रिया में किए गए थे महत्वपूर्ण बदलाव- ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा था कि टेंडर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। ऐसी प्रबल संभावना है कि बिक्री के समय जमीन के टुकड़ों का मूल्य कम करके आंका गया और बाद में वे लालू यादव के हाथों में चले गए।



लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और सामूहिक आकांक्षाओं का आधार है देश का संविधानः ओम बिरला



'संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल सिद्धांतों को समाहित किया गया है। इन सिद्धांतों ने सभी नागरिकों को साझा संवैधानिक पहचान दी है और राष्ट्र के भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार किया है।'

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि भारत का संविधान केवल देश का सर्वोच्च कानून नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और सामूहिक आकांक्षाओं का आधार भी है। इसने असाधारण विविधता के बावजूद देश की एकता को बनाए रखते हुए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को निरंतर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है।

संविधान दिवस के अवसर पर संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए बिरला ने युवाओं से संविधान के आदर्शों और मूल्यों को केवल पढ़ने तक सीमित न रखने बल्कि उन्हें अपने विचारों, आचरण और दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती केवल नागरिकों को मिले अधिकारों पर निर्भर नहीं करती बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों तथा दायित्वों के निर्वहन की इच्छाशक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने एक सुदृढ़ संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी, जो शांति, समृद्धि और प्रगति की दिशा में भारत की यात्रा का मार्गदर्शन कर रहा है। संविधान ने भाषाओं, बोलियों, धर्मों, परंपराओं और संस्कृतियों की अपार विविधता का सम्मान करते हुए देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए स्थायी ढांचा प्रदान किया है। संविधान सदन की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह भवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक क्षणों और स्वतंत्रता के बाद उन महत्वपूर्ण विचार-विमर्शों का साक्षी रहा है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की दिशा और नियति तय की।

यह परिसर उन बलिदानों, दृढ़ विश्वासों और दूरदर्शी आकांक्षाओं का प्रमाण है, जिनसे भारतीय गणराज्य का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि संविधान के सार्वभौमिक आदर्श और लोकतांत्रिक सिद्धांत न केवल भारत बल्कि दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों के लिए भी मार्गदर्शक हैं। बिरला ने संविधान सभा की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान सभा के सदस्यों ने दो वर्ष और 11 महीने तक व्यापक विचार-विमर्श किया।

इस दौरान विभिन्न दृष्टिकोणों को सुना गया, जटिल मुद्दों पर चर्चा हुई और संवाद, तर्कपूर्ण बहस तथा आपसी समझ के माध्यम से समाधान निकाले गए। वैचारिक मतभेदों के बावजूद सदस्यों ने आम सहमति बनाने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की अनुकरणीय भावना का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि संविधान सभा की यह यात्रा भारत में संवाद, वाद-विवाद और सहमति बनाने की लोकतांत्रिक परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है।

दिल्ली में 27 नवंबर से सजेगा 'कारीगर बाज़ार'

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आगामी शुक्रवार से 10 दिवसीय 'कारीगर बाज़ार' का दूसरा संस्करण शुरू होगा। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध पारंपरिक कला और हस्तशिल्प विरासत को बढ़ावा देना है।

क्राफ्ट एंड आर्टिजन रिवाइवल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में देश के 26 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 250 से अधिक कारीगर तथा शिल्पकार हिस्सा लेंगे। इनमें राष्ट्रीय पुरस्कार एवं संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित शिल्पकारों के साथ-साथ जीआई टैग प्राप्त कला के विशेषज्ञ, पारंपरिक बुनकर, महिला कारीगर, स्वयं सहायता समूह और उभरते उद्यमी शामिल होंगे। बाज़ार में आगंतुकों को देश के विभिन्न हिस्सों की हस्तनिर्मित कलाकृतियों और पारंपरिक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला देखने को मिलेगी। इनमें मुख्य रूप से वस्त्र एवं कढ़ाई में बनारसी, चंदेरी, महेश्वरी, इकत, ब्लॉक प्रिंटिंग, चिकनकारी और कच्छ कढ़ाई, चित्रकला एवं शिल्प में मधुबनी एवं गोंड चित्रकला, टेराकोटा, ब्लू पॉटरी और धातु एवं लकड़ी की नक्काशी, अन्य उत्पादों में पारंपरिक आभूषण और पर्यावरण के अनुकूल (इको-फ्रेंडली) हस्तशिल्प शामिल हैं। इस संस्करण में 'कारीगर एक्सपीरियंस सेंटर' विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। यहां आने वाले लोग बुनाई, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन बनाने, चित्रकला और नक्काशी जैसी पारंपरिक कलाओं का लाइव प्रदर्शन देख सकेंगे।

घटते सत्रों पर शशि थरूर बोले- सरकार संसद को बहस का मंच नहीं, सिर्फ रबर स्टैंप बनाना चाहती है

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को संसद सत्रों की घटती अवधि पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद की उस भूमिका को कमजोर कर रही है, जो बहस, चर्चा और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रमुख मंच होती है। शशि थरूर ने कहा कि 1950 के दशक में सालाना संसद की कार्यवाही लगभग 120 से 170 दिन होती है। अब साल में लगभग 70 दिन ही होती है। उन्होंने कहा, 'जहां तक हमारी बात है, हमें संसदीय लोकतंत्र के प्रति सरकार का रवैया बेहद अजीब लगता है।' उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात में उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल से तुलना की। थरूर ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान गुजरात विधानसभा के सत्रों की अवधि भी घटा दी गई थी। उनके अंतिम वर्षों में विधानसभा सालाना केवल लगभग 50 से 55 दिन ही बैठती थी। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि संसद एक बहस के मंच के रूप में काम करे, जहां नागरिकों की चिंताओं को उठाया जा सके और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराया जा सके।

सीवेज प्रदूषण के मुद्दे पर एनजीटी का सख्त रुख, जल बोर्ड को लगाई फटकार; चीफ इंजीनियर से जवाब तलब

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में सीवेज प्रदूषण के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। बिना शोधित सीवेज को नालों में छोड़े जाने के मामले में एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से जवाब तलब किया है। अधिकरण ने इस व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए डीजेबी को फटकार लगाई है। एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को मौके पर जाकर जांच करने का आदेश दिया। समिति को नालों के पानी के सैंपल लेकर उनकी जांच करानी होगी। एनजीटी ने डीजेबी से पूछा कि काम पूरा होने का दावा करने के बावजूद नालों में गंदा पानी कैसे बह रहा है।

सुनवाई के दौरान तस्वीरें पेश की गईं। इनमें दावा किया गया कि पंत नगर और लाजपत नगर के ड्रेन नंबर-22 में अब भी बिना शोधित सीवेज बह रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में सीवेज प्रदूषण के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। बिना शोधित सीवेज को नालों में छोड़े जाने के मामले में एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से जवाब तलब किया है। अधिकरण ने इस व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए डीजेबी को फटकार लगाई है। एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को मौके पर जाकर जांच करने का आदेश दिया। समिति को नालों के पानी के सैंपल लेकर उनकी जांच करानी होगी। एनजीटी ने डीजेबी से पूछा कि काम पूरा होने का दावा करने के बावजूद नालों में गंदा पानी कैसे बह रहा है। सुनवाई के दौरान तस्वीरें पेश की गईं। इनमें दावा किया गया कि पंत नगर और लाजपत नगर के ड्रेन नंबर-22 में अब भी बिना शोधित सीवेज बह रहा है।

जल बोर्ड की लेट पेमेंट सरचार्ज छूट योजना का 5,66,349 उपभोक्ता ने उठाया लाभ

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड की लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) छूट योजना के माध्यम से घरेलू परिवारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी आर्थिक राहत मिल रही है। साथ ही उपभोक्ता स्वेच्छा से अपने लंबे समय से लंबित पानी के बिलों का भुगतान करने के लिए आगे आ रहे हैं। योजना के ताजा आंकड़ों के अनुसार, घरेलू और व्यावसायिक श्रेणियों के कुल 5,66,349 उपभोक्ता इसका लाभ उठा चुके हैं। इन उपभोक्ताओं को 3,618.73 करोड़ रुपये की एलपीएससी छूट दी गई है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड को बकाया बिलों के मूलधन राशि के रूप में 1,076.15 रुपये करोड़ प्राप्त हुए हैं।

व्यावसायिक श्रेणी में भी उपभोक्ताओं की अच्छी भागीदारी देखने को मिली है। इस श्रेणी के लिए योजना बाद में शुरू की गई थी, इसके बावजूद हजारों व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने आगे आकर इसका लाभ उठाया है। घरेलू उपभोक्ता (श्रेणी-ढ्ढ) - कुल 13,39,018 पात्र घरेलू उपभोक्ताओं में से 5,48,074 उपभोक्ता योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस प्रकार लगभग 41 प्रतिशत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं ने योजना में भागीदारी की है। इस श्रेणी से दिल्ली जल बोर्ड को मूलधन के रूप में 854.54 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जबकि उपभोक्ताओं को 1,886.89 करोड़ रुपये की एलपीएससी छूट दी गई है। व्यावसायिक उपभोक्ता (श्रेणी-II) - कुल 70,312 पात्र व्यावसायिक उपभोक्ताओं में से 18,275 उपभोक्ता योजना का

दिल्ली विश्वविद्यालय 12 से 14 फरवरी तक दूसरे साहित्य महोत्सव का करेगा आयोजन

आयोजन में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं होना चाहिए, जो सामाजिक सौहार्द और राष्ट्र हित के खिलाफ हो।

अनप्लग इंडिया

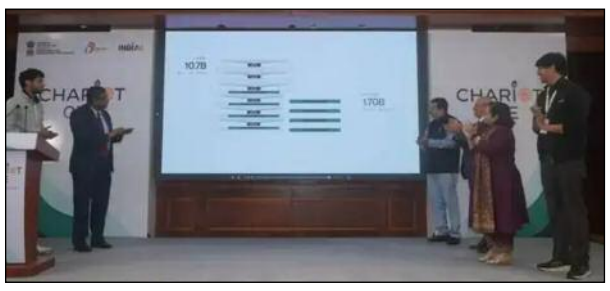
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के दूसरे साहित्य महोत्सव (डीयूएलएफ 2.0) का आयोजन 12 से 14 फरवरी, 2027 तक किया जाएगा। इसका निर्णय डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित साहित्य महोत्सव कमेटी की बैठक में गुरुवार को लिया गया। महोत्सव के आयोजन को लेकर आयोजित इस पहली बैठक में साहित्य महोत्सव के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई।



बैठक को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित डीयू के पहले साहित्य महोत्सव का आयोजन बहुत सफल रहा था। उन्होंने आशा जताई कि इस बार का आयोजन और भी विशाल होगा। कुलपति ने डीयूएलएफ 2.0 के आयोजन को लेकर सुझाव देते हुए कहा कि जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया है, साहित्य महोत्सव के दौरान उन्हें भी सम्मान दिया जाए। उन्होंने कहा कि साहित्य महोत्सव के आयोजन में दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण विभागों की भागीदारी भी आयोजन में सुनिश्चित की जाए। कुलपति ने कहा कि साहित्य महोत्सव का आयोजन देश हित को ध्यान में रख कर होने चाहिए।

सरकारी योजनाओं की जानकारी अब 22 से अधिक भाषाओं में मिलेगी

सामाजिक न्याय मंत्रालय और भाषिणी के बीच हुआ समझौता



अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं और सेवाओं को देश के हर नागरिक तक उसकी अपनी भाषा में पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया है। इस साझेदारी के जरिए सामाजिक न्याय मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भाषिणी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित भाषा तकनीक को जोड़ा जाएगा। इससे नागरिकों और लाभार्थियों को 22 से अधिक भाषाओं में सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी मिल सकेगी। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भाषा की बाधा को दूर करना और सरकारी सेवाओं को अधिक समावेशी एवं सुलभ बनाना है। समझौते के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा, विभाग के सचिव सुधांश पंत और डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ नाग सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस साझेदारी के तहत भाषिणी की भाषा तकनीक को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म 'समावेश' (सिंगल एक्सेस मैकेनिज्म फॉर ऑल वर्टिकल्स ऑफ एम्पावरमेंट एंड सोशल हार्मनी) के साथ जोड़ा जाएगा। समावेश पोर्टल का उद्देश्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और संगठनों से जुड़ी जानकारियों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। अब भाषिणी की तकनीक जुड़ने से लोग अपनी पसंद की भाषा में योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकेंगे।

संविधान के अपमान को लेकर अपने अतीत पर नजर डाले कांग्रेसः शिवराज

'संविधान के अपमान के मामले में कांग्रेस खुद कटघरे में खड़ी है।'



अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को संविधान दिवस पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान के अपमान को लेकर दूसरों पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस खुद कटघरे में खड़ी है। लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस का इतिहास ही संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के अपमान से जुड़ा रहा है। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले उसको अपने अतीत पर नजर डालनी चाहिए।

चौहान ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि देश में आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। आपातकाल के दौरान डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में बंद किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद को प्रधानमंत्री पद पर बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा से बाहर करने का प्रयास किया था। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस शासनकाल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश में 100 से ज्यादा निर्वाचित सरकारों को भंग किया। अकेले इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगभग 50 निर्वाचित सरकारें बर्खास्त की गईं। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को कपड़ों की तरह बदला। लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस का इतिहास ही संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के अपमान से जुड़ा रहा है। ऐसे में दूसरों पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने अतीत पर नजर डालनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने यूपीए सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार में निर्वाचित सरकार के ऊपर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बैठाई गई थी। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की कैबिनेट के फैसले को राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़कर फेंक दिया था।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर्तव्य भवन में मनाया 'संविधान दिवस'



अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संविधान दिवस मनाया। इस अवसर पर अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रतिनिधियों समेत मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।

सीएससी की बैठक में भारत सहित चार देशों ने 2026-27 के सहयोग का रोडमैप अपनाया



अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (सीएससी) की आठवीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) स्तर की बैठक में भारत सहित चार सदस्य देशों ने वर्ष 2026-27 के लिए सहयोग का रोडमैप अपनाया है। इसमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन सहित पांच प्रमुख क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। मालदीव की मेजबानी में 25 नवंबर को विला नौटिका पैराडाइज आइलैंड में आयोजित इस बैठक में भारत, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने हिस्सा लिया। मॉरीशस ने बैठक में वर्चुअल माध्यम से भागीदारी की। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इब्राहिम लतीफ, श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के सचिव एयर वाइस मार्शल संपत थुयाकोंथा और बांग्लादेश के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एमडी फैजुर रहमान ने अपने-अपने देशों के प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया ने अतिथि देशों के रूप में बैठक में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से विदेश मामलों एवं व्यापार विभाग में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया समूह की प्रथम सहायक सचिव सारा स्टोरी तथा मलेशिया की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा एवं संप्रभुता प्रभाग के निदेशक खैरुल अजहर (निक) बिन अबू बकर शामिल हुए।

ई-रिक्शा में पत्नी-बच्चों को बैठाकर करते थे लूटपाट

दो महिलाओं समेत परिवार के चार सदस्य गिरफ्तार

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। ई-रिक्शा में पत्नी और बच्चों को साथ बैठाकर यात्रियों से लूटपाट करने वाले एक परिवार का पूर्वी जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं समेत परिवार के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि परिवार के सदस्य ई-रिक्शा में सवारी बनकर बैठते थे और महिलाओं व बच्चों की मौजूदगी में यात्रियों को शक नहीं होने देते थे। इसके बाद सुनसान जगह पर ले जाकर चाकू की नोक पर लूटपाट करते थे। आरोपियों ने 14 नवंबर की रात धर्मशिला पुल के पास एक यात्री से पांच हजार रुपये, आधार कार्ड और वोटर पहचान पत्र लूट लिया था। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित राजेश कुमार ने 14 नवंबर की रात करीब 10:59 बजे पीसीआर कॉल कर लूट की सूचना दी थी। उसने बताया कि ई-रिक्शा चालक ने दो महिलाओं और दो बच्चों की मौजूदगी में चाकू दिखाकर उससे पांच हजार रुपये लूट लिए। जांच में पता चला कि राजेश रात करीब 10:30 बजे नोएडा टी-पॉइंट से आनंद विहार बस टर्मिनल जाने के लिए डीएल7ईआर नंबर के ई-रिक्शा में सवार हुआ था। ई-रिक्शा में पहले से दो महिलाएं और दो बच्चे बैठे हुए थे। रास्ते में चालक ने ई-रिक्शा धर्मशिला अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। उसने राजेश को बताया कि उसे पत्नी और बच्चों को घर छोड़ना है। इसके बाद वह उसे धर्मशिला पुल के पास सुनसान जगह पर ले गया। वहां चाकू दिखाकर पांच हजार रुपये, आधार कार्ड और वोटर पहचान पत्र छीन लिए। आरोप है कि ई-रिक्शा में मौजूद दोनों महिलाओं ने भी पीड़ित को डराया और चालक की मांग मानने के लिए दबाव बनाया। इस मामले में न्यू अशोक नगर थाने में एफआईआर नंबर 823/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4)/3(5) में मामला दर्ज किया गया। डीसीपी पूर्वी जिला राजीव कुमार के मुताबिक, पुलिस ने ई-रिक्शा के पंजीकरण नंबर के आधार पर उसके मालिक कल्याणपुरी निवासी 55 वर्षीय अंसार का पता लगाया।

संविधान दिवस पर अरविंद केजरीवाल का आह्वान, बोले- बाबा साहब के संविधान के सच्चे प्रहरी बनें देशवासी

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। संविधान दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए संविधान के मूल्यों, लोकतांत्रिक अधिकारों और उसकी मूल भावना की रक्षा करने का आह्वान किया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों, न्याय और सम्मान का आधार है। संविधान है, तो हमारे अधिकार हैं, संविधान है, तो न्याय है और संविधान है, तो हम हैं और हमारा यह देश है। उन्होंने देशवासियों से बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए महान संविधान के सच्चे प्रहरी बनने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा कि देश में सत्ता और राजनीतिक पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन भारत का संविधान हमेशा अटल और मजबूत रहना चाहिए। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र, समानता और नागरिकों के अधिकारों की बुनियाद है। इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संविधान की गरिमा और उसके मूल्यों को बनाए रखना जरूरी है, ताकि देश का लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत बना रहे और हर नागरिक को उसके अधिकार मिलते रहें।

वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी संविधान दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया भारतीय संविधान दूरदर्शी सोच और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण है। संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समानता और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया है।

संक्षिप्त डायरी

प्रदूषण पर निगम सख्त, एक महीने में किए 353 चालान

अनप्लग इंडिया

मानेसर। मानेसर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शहर में विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। वहीं, पेड़ों पर जमा धूल को एंटी स्मॉग गन की मदद से साफ किया जा रहा है। इसके अलावा सेक्टरों की सड़कों के किनारे जमा मिट्टी को भी हटाया जा रहा है, ताकि वाहनों की आवाजाही के दौरान धूल न उड़े और लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिल सके। नगर निगम की ओर से ग्रेप नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरती जा रही है। निगम के अनुसार, पिछले एक महीने में ग्रेप नियमों की अवहेलना करने वालों के 353 चालान किए गए हैं। इन पर करीब 80 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया गया है। निगम की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर प्रदूषण फैलाने वालों की जांच कर रही हैं। जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलता है, वहां मौके पर चालान किया जा रहा है।

न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे वकील

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। जिला बार एसोसिएशन, गुरुग्राम ने बृहस्पतिवार 26 नवंबर को न्यायिक कार्य निलंबित करने की घोषणा की है। यह निर्णय नारनौल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मनजीत कुमार और पूर्व सचिव सुमित चौधरी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के विरोध में है। गुरुग्राम एसोसिएशन ने बार एसोसिएशनों की स्वायत्तता के समर्थन में यह कदम उठाया है।

दादा भैया तालाब का 2 करोड़ में होगा जीर्णोद्धार

अनप्लग इंडिया

मानेसर। नगर निगम मानेसर वार्ड नंबर-12 के गांव मानेसर स्थित दादा भैया तालाब का विकास और जीर्णोद्धार कराएगा। इस कार्य पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह योजना पुराने तालाब की मरम्मत कर उसे नया रूप देगी। इसका उद्देश्य गांव के पुराने जलस्त्रोत को बचाना और पानी जमा करने की बेहतर व्यवस्था करना है। गांव मानेसर में भूजल स्तर लगातार गिरने से ग्रामीणों को पानी की समस्या हो रही है। तालाब के जीर्णोद्धार से बारिश का पानी जमा होगा, जिससे भूजल स्तर बढ़ने में मदद मिलेगी। निगम जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करेगा। इस परियोजना से ग्रामीणों को घूमने और बैठने के लिए बेहतर जगह मिलेगी। इससे बुजुर्गों और बच्चों को खाली समय बिताने का अच्छा स्थान मिलेगा। गांव मानेसर के दादा भैया तालाब का करीब दो करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू किया जाएगा। तालाब के विकसित होने से बारिश का पानी जमा हो सकेगा और जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आरडब्ल्यूए से संवाद कर निगमायुक्त ने दिए समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. पंकज ने बुधवार को 30 से अधिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। इस बैठक का उद्देश्य शहर की नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना और स्थानीय समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने अपने इलाकों की विभिन्न समस्याएं निगमायुक्त के समक्ष रखीं। चर्चा के दौरान सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, सड़क बत्ती और पेयजल आपूर्ति जैसे कई मुद्दे उठाए गए। सामुदायिक केंद्रों, बागवानी, पार्कों, सड़कों और सीवर व्यवस्था से संबंधित समस्याओं पर भी विस्तार से बात हुई। निगमायुक्त ने सभी संयुक्त आयुक्तों और कार्यकारी अभियंताओं को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की आरडब्ल्यूए के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें। डॉ. पंकज ने अधिकारियों को स्थानीय समस्याओं का प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अनावश्यक देरी से बचने और प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। निगमायुक्त डॉ. पंकज ने बताया कि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधाएं देना है। उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि नागरिकों की अपेक्षाओं से सीधे जुड़े होते हैं। इसलिए उनके सुझाव और प्रतिक्रिया निगम के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को आरडब्ल्यूए के साथ नियमित समन्वय रखने के निर्देश दिए गए। निगम का प्रयास है कि केवल शिकायतें दूर न हों, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाओं का अनुभव भी हो।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्राः बुजुर्गों को वाराणसी दर्शन

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 15 दिसंबर को 4 दिवसीय निशुल्क वाराणसी यात्रा होगी। प्रदेश के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को यह यात्रा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ट्रेन को हरीझंडी दिखाएंगे। 60 वर्ष या अधिक आयु के श्रद्धालु इसके पात्र हैं। उनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र सरल पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

विवाद सुलझाने के लिए बुलाई पंचायत में मारपीट

अनप्लग इंडिया

रबूपुरा। गांव सिरौली बांगर में पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत में कुछ लोगों ने पिता पुत्र पर हमला कर घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि गांव फलैदा निवासी कमलसिंह और उनके बेटे नितिन को 10 नवंबर को गांव सिरौली बांगर निवासी उनके रिश्तेदार दुर्योधन ने पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए पंचायत करने के मकसद से अपने गांव बुलाया था। वहां पहले से ही उनके कुछ अन्य रिश्तेदार भी मौजूद थे। आरोप है कि पंचायत के दौरान किसी बात को लेकर उनके रिश्तेदार बुलंदशहर के गांव बुर्ज निवासी जयपाल व योगेश और गांव खबरा निवासी मोनू पिता पुत्र के साथ गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पिता पुत्र पर हमला कर दिया। इस दौरान जान से मारने की धमकी भी दी गई। हमले में दोनों को गंभीर चोटें आई। शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घर में घुसकर दंपति और बेटियों से मारपीट

अनप्लग इंडिया

रबूपुरा। क्षेत्र के गांव मेहंदीपुर बांगर में घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। घटना में घायल दंपति और दो बेटियों को ग्रेटर नोएडा स्थित जिस्म अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव मेहंदीपुर बांगर निवासी जुबेदा बीते 10 नवंबर को अपने घर में घरेलू कार्य कर रही थी। सुबह करीब 8 बजे गांव के ही निवासी मोहारुद्दीन, फारूक, मोहिन और परवेज पीड़िता के घर में घुसकर गाली गलौज करने लगे। विरोध किया तो लाठी डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। जब उसे बचाने उसकी बेटी दानिश्ता, फिजा व उसके पति जमील आए तो आरोपितो ने उनकी भी पिटाई कर दी। घटना में दंपति और दोनों बेटियां घायल हो गई। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्रेटर नोएडा में निवेश की संभावनाएं तलाशने पहुंचा दक्षिण कोरिया का सरकारी प्रतिनिधिमंडल

अनप्लग इंडिया



ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए दक्षिण कोरिया का एक उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में प्राधिकरण के तीनों अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (एसीईओ) के साथ बैठक की। इस दौरान ग्रेटर नोएडा और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप (आईआईटीजीएनएल) में उपलब्ध औद्योगिक सुविधाओं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश नीतियों और लैंड बैंक के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रतिनिधिमंडल में दक्षिण कोरिया के सांसद किम जुंग हो, मून जियोंगबोग, कैंग सियोंगक्यू और ली जुयोंग समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे। भारतीय दूतावास के प्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. बलकार सिंह के निर्देश पर एसीईओ प्रेरणा सिंह, सुमित यादव और नुपुर गोयल ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

बैठक के दौरान एसीईओ प्रेरणा सिंह ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से ग्रेटर नोएडा और आईआईटीजीएनएल की औद्योगिक खूबियों और निवेश के अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप देश की स्मार्ट औद्योगिक टाउनशिप में शामिल है। इसे प्लग एंड प्ले सिस्टम के आधार पर विकसित किया गया है, जहां उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को कम समय में भूखंड आवंटित करने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं पहले से विकसित की जा चुकी हैं। ऐसे में भूखंड आवंटित होते ही उद्यमी अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक होने के साथ ही यह टाउनशिप सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बेहतर स्थिति में है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं की सराहना

दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा के नियोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ-सफाई और नागरिक सुविधाओं की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल ने ईकोटेक-3 स्थित न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के प्लांट का भी भ्रमण किया और औद्योगिक गतिविधियों को करीब से देखा। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने ग्रेटर नोएडा में निवेश की संभावनाओं में रुचि दिखाई और यहां औद्योगिक निवेश करने की इच्छा जाहिर की। इस दौरे को क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक निवेश की संभावनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

संविधान दिवस पर डॉ. महेश शर्मा ने विद्यार्थियों से किया संवाद, प्रतिभाशाली छात्रों को किया सम्मानित



अनप्लग इंडिया

नोएडा। संविधान दिवस के अवसर पर गौतमबुद्ध नगर के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने गुरुवार को सेक्टर-62 स्थित दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने संविधान में निहित मूल आदर्शों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में युवाओं की भूमिका पर विचार रखे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए डॉ. महेश शर्मा ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों का महत्व बताया। उन्होंने नागरिकों के अधिकारों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भूमिका पर चर्चा

डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि संविधान में दिए गए आदर्श देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार हैं। युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे इन मूल्यों को समझें और अपने व्यवहार तथा सामाजिक जीवन में अपनाएं।

उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक रहने और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने का संदेश दिया।

उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को किया सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इन विद्यार्थियों को संविधान की शपथ भी दिलाई गई।

इस अवसर पर पैरालंपिक खिलाड़ी सुवर्णा राज, डीएमई की निदेशक डॉ. कोमल विग, डॉ. राजेंद्र कौर रंधावा, शिवेंद्र सिंह, संजय बाली, रोहित शर्मा, रोहित ठाकुर और मनोज उपाध्याय सहित कॉलेज के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को संविधान के मूल्यों, नागरिक जिम्मेदारियों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक करना रहा।

चुनाव से पहले गौतमबुद्ध नगर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 45 निरीक्षकों का तबादला



अनप्लग इंडिया। डेस्क

नोएडा। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में अधिकारियों की तैनाती को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। जिले में तैनात 45 निरीक्षकों का तबादला प्रदेश के दूसरे कमिश्नरेट और पुलिस जोन में कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय की ओर से बुधवार को जारी आदेश में सभी संबंधित निरीक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ स्थित डीजीपी मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार, एक जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके निरीक्षकों को स्थानांतरित किया गया है। पुलिस स्थापना बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी सूची में इन निरीक्षकों को प्रदेश के विभिन्न पुलिस कमिश्नरेट और जोन में नई तैनाती दी गई है।

आगरा कमिश्नरेट में सबसे ज्यादा तैनाती

तबादला सूची में आगरा, लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, मेरठ और प्रयागराज समेत कई कमिश्नरेट और पुलिस जोन शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक निरीक्षकों को आगरा कमिश्नरेट भेजा गया है। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, मेरठ और प्रयागराज में भी निरीक्षकों की तैनाती की गई है।

जिले के 20 थानेदारों का कार्यकाल भी तीन साल से अधिक

गौतमबुद्ध नगर में कुल 27 थाने हैं। इनमें करीब 20 थानों के प्रभारी ऐसे बताए जा रहे हैं, जिन्होंने जिले में तीन साल से ज्यादा समय पूरा कर लिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में जिले के थाना प्रभारियों और अन्य निरीक्षकों के तबादले की एक और सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है।

हालांकि, अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग में तैनाती और तबादलों की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में जिले के थानों के प्रभारियों में भी बदलाव हो सकता है।

सफाई और विकास कार्यों में आरडब्ल्यूए की भागीदारी की मांग

अनप्लग इंडिया



गुरुग्राम। शहर की बुनियादी सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से यूनाइटेड गुरुग्राम आरडब्ल्यूए (यूजीआर) ने निगम आयुक्त डॉ. पंकज को पत्र सौंपकर विकास कार्यों में आरडब्ल्यूए की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। बुधवार को यूजीआर के संयोजक प्रवीण यादव और सह-संयोजक चैताली मंदोत्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने निगम आयुक्त से मुलाकात की। यूजीआर पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष रखे गए पांच प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर निगमायुक्त के साथ सार्थक चर्चा हुई और उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया है। पत्र में मांग की गई है कि किसी भी क्षेत्र में विकास कार्यों के एस्टीमेट स्थानीय आरडब्ल्यूए के परामर्श से आवश्यकता के अनुरूप तैयार किए जाएं। साथ ही, वर्क ऑर्डर की प्रति संबंधित आरडब्ल्यूए को देने और इसे एमसीजी पोर्टल पर सार्वजनिक करने की मांग की गई है। यूजीआर का आरोप है कि वर्क ऑर्डर सार्वजनिक न होने के कारण ठेकेदार टेंडर की 10 प्रतिशत शर्तों का भी पालन नहीं करते। संगठन ने ठेकेदारों को भुगतान से पहले आरडब्ल्यूए से संतुष्टि प्रमाण पत्र' लेने की पुरानी व्यवस्था को दोबारा लागू करने पर जोर दिया। दस फीसदी कम दर पर सफाई को तैयार आरडब्ल्यूए को मिले काम सफाई व्यवस्था को लेकर सुझाव दिया गया कि जो आरडब्ल्यूए मौजूदा ठेकेदारों से 10 प्रतिशत कम दर पर सड़कों की सफाई की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, उन्हें यह कार्य सौंपा जाए। इसके लिए आरडी सिटी आरडब्ल्यूए के वर्ष 2025 के त्रिपक्षीय समझौते का उदाहरण दिया गया, जहां बेहतर सफाई के बावजूद निगम द्वारा अब तक भुगतान नहीं किया गया है। संपत्तिकर में कचरा शुल्क न जोड़ने की अपील घरों से कूड़ा एकत्रित पर यूजीआर ने दैनिक गीले व सप्ताह में दो बार सूखे कचरे के उठान, ई-कचरे के लिए प्रत्येक जोन में कम से कम तीन एजेंसियों को सूचीबद्ध करने और गांवों व अनधिकृत कॉलोनियों में बिना शुल्क की परवाह किए अनिवार्य कचरा उठान की मांग की। इसके अलावा, संपत्तिकर में कचरा संग्रहण शुल्क जोड़ने के प्रस्ताव को रद्द करने की अपील की गई है

नूंह के गांवों में शराब ठेकों के खिलाफ ग्रामीण लामबंद, डीसी को सौंपा ज्ञापन

अनप्लग इंडिया



नूंह। नूंह जिले के गांव कुरथला और आलदोका में शराब के ठेकों और कथित तौर पर बढ़ती नशाखोरी को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज होने लगा है। दोनों गांवों के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला उपायुक्त अखिल पिलानी को ज्ञापन सौंपकर गांवों में शराब के ठेके हटाने और नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि स्कूल, मंदिर और गांव की फिरनी के इतने नजदीक शराब का ठेका संचालित करने की अनुमति कैसे दी गई। ग्रामीणों के अनुसार, कुरथला गांव में शराब का ठेका स्कूल, मंदिर और गांव की फिरनी से 100 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। इस संबंध में पहले भी गांव में पंचायत आयोजित कर ठेके को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूछा कि जब गांव के लोग एकजुट होकर ठेका हटाने की मांग कर रहे हैं तो उनकी शिकायत पर समाधान क्यों नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों ने गांवों में शराब के ठेकों के अलावा चिट्टा, गांजा, सूखा नशा और अवैध शराब की कथित बिक्री पर भी चिंता जताई। उनका आरोप है कि गांवों में नशे का प्रभाव किशोरों तक पहुंच रहा है और 13 से 17 वर्ष तक के बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि यह उम्र बच्चों के पढ़ने-लिखने और खेलकूद में आगे बढ़ने की है, यदि तत्काल ठेका हटाना संभव नहीं है तो इसे कम से कम आबादी से दो किलोमीटर दूर स्थापित किया जाए। साथ ही आगामी आबकारी नीति में दोनों गांवों को शराब के ठेकों से मुक्त रखने का प्रावधान किया जाए। ग्रामीणों ने कथित तौर पर बिक रहे सूखे नशे और अवैध शराब के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने की मांग की। जिला उपायुक्त ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आगामी आबकारी नीति में शराब के ठेके हटाने की उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा आबकारी नीति के तहत भी मामले की जांच करवाकर उचित कदम उठाने की बात कही।

गाजियाबाद में पति, बेटे और भांजे को धीमा जहर देने के आरोप में महिला गिरफ्तार

अनप्लग इंडिया

गाजियाबाद। इंदिरापुरम में पति, बेटे और भांजे को कथित तौर पर लंबे समय तक खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर देने के मामले में पुलिस ने 42 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रेनू भटनागर के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि वह करीब एक साल तक परिवार के तीन सदस्यों के भोजन में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सीसा (लेड) का पाउडर मिलाती रही।

पुलिस के अनुसार, आरोपी का मकसद पति के ट्रैवल कारोबार पर नियंत्रण हासिल करना था। इसके अलावा पति के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी थी, जिसमें रेनू नॉमिनी थी। पुलिस इस मामले में संपत्ति और बीमा की रकम को संभावित वजह मानकर जांच कर रही है।

ट्रांस हिंडन के डीसीपी रिजुल के मुताबिक, रेनू ने पूछताछ में पति को जहर देने की बात स्वीकार की है। पुलिस का कहना है कि बेटे और भांजे को भी इसी तरह निशाना बनाया गया था। मामले में नामजद अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

ब्लड टेस्ट में सामने आई सीसे की अधिक मात्रा

ट्रैवल कारोबारी सुशील कुमार भटनागर के मुताबिक, 21 अगस्त 2025 को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। जांच कराने पर खून में लेड की मात्रा सामान्य से काफी अधिक पाई गई। इसके बाद उन्हें वैशाली स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब दो महीने तक इलाज चला। हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भी रखना पड़ा।

सुशील के अनुसार, डॉक्टरों ने उन्हें क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग की जानकारी दी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ी और फिर भर्ती कराना पड़ा। बाद में उनका बेटा वंश (16) और भांजा देव भटनागर (21) भी बीमार पड़ गए। तीनों की मेडिकल रिपोर्ट में लेड पॉइजनिंग की पुष्टि हुई।

बेटी की बात से परिवार को हुआ शक

डीसीपी रिजुल के मुताबिक, शुरुआत में सुशील के पास पत्नी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। सितंबर 2026 के पहले सप्ताह में उनकी 12 वर्षीय बेटी ने परिवार को बताया कि मां पहले अपने और बेटी के लिए खाना अलग रखती थीं। इसके बाद बाकी सदस्यों को परोसे जाने वाले भोजन पर कुछ छिड़कती थीं।

परिवार ने जब रेनू से इस बारे में सवाल किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वह दिल्ली में अपनी बहन के घर चली गई। सुशील ने 24 सितंबर 2026 को इंदिरापुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई।

ट्रैवल कारोबार पर कब्जे की थी योजना: पुलिस-पुलिस के अनुसार, सुशील का ट्रैवल कारोबार सालाना करीब 5 से 6 करोड़ रुपये का है। भांजा देव भी कारोबार की देखरेख करता था। जांच में सामने आया कि रेनू कारोबार पर पूरा नियंत्रण चाहती थी। पुलिस का दावा है कि इसी वजह से उसने पति और भांजे को निशाना बनाने की योजना बनाई। बेटे को भी इसलिए निशाना बनाया गया, क्योंकि वह पिता का पक्ष लेता था। पुलिस के मुताबिक, सुशील के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपये की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, जिसमें रेनू नॉमिनी थी। एसीपी अभय डागा ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने संपत्ति और बीमा की रकम के लालच में पति को धीमा जहर देने की बात स्वीकार की है।

पिता की ज्वैलरी दुकान से लेड मिलने की आशंका

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रेनू के पिता की ज्वैलरी की दुकान है। वहां धातु की ढलाई से जुड़े कामों में लेड का इस्तेमाल होता है। पुलिस यह पता लगा रही है कि आरोपी ने सीसे का पाउडर इसी दुकान से हासिल किया था या कहीं अन्य जगह से इसकी व्यवस्था की थी। पुलिस के मुताबिक, सितंबर में घर छोड़ने से पहले रेनू ने कथित तौर पर जहर को कूड़ेदान में फेंक दिया था।

24 नवंबर को दिल्ली से हुई गिरफ्तारी-सुशील की शिकायत पर 24 सितंबर 2026 को इंदिरापुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 123 और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में रेनू की मां लता सक्सेना, भाई रवि सक्सेना, जीजा सुशील गिरधर और परिचित बब्लू के नाम भी शामिल किए गए थे। पुलिस ने बच्ची और डॉक्टरों के बयान दर्ज किए तथा तीनों पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट की जांच की। इसके बाद 24 नवंबर 2026 को रेनू को दिल्ली के विवेक विहार स्थित झिलमिल कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया, जहां वह अपनी बहन के घर पर रह रही थी। पुलिस अन्य नामजद लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।

लंबे समय तक लेड शरीर में पहुंचने से गंभीर नुकसान

डॉक्टरों के मुताबिक, सीसा एक जहरीली धातु है। इसकी थोड़ी-थोड़ी मात्रा लंबे समय तक शरीर में पहुंचने से भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग के शुरुआती लक्षण कई बार स्पष्ट नहीं होते और इसका असर धीरे-धीरे शरीर के अलग-अलग अंगों पर पड़ता है। यह पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हृदय और प्रजनन प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। गाजियाबाद के संजय नगर अस्पताल के पूर्व सीएमएस डॉ. संजय तियोतिया के अनुसार, शरीर में सीसे की मात्रा बहुत अधिक होने या इलाज में देरी होने पर दौरे, कोमा और मस्तिष्क को स्थायी नुकसान जैसी गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती हैं।

संपादकीय

भाजपा ने तैयार किया आक्रामक मेगा प्लान



मथुरा सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में अहम मंथन बैठक करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए आक्रामक मेगा प्लान तैयार किया है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के संकल्प तथा यूजीसी, मतदाता सूची की कमियों और टिकट वितरण पर गहन चर्चा के बाद पार्टी आगे की रणनीति बना चुकी है। अगले माह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तथा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के संगठन व कार्यकर्ता सर्वोपरि के मंत्र के साथ पार्टी प्रदेश की राजनीति में अपने को अंगद के पांव की तरह जमाने के लिए मैदान में उतरने जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गो अनुसंधान केंद्र परखम में आयोजित मंथन बैठक में संकल्प लिया गया है कि तीसरी तीसरी बार सत्ता मिलते ही मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनकर रहेगा। मथुरा की मंथन बैठक में यह भी तय किया गया है कि सर्वाधिक फोकस कार्यकर्ताओं पर ही रहेगा। अब भाजपा में कार्यकर्ताओं को केवल देवतुल्य कहा ही नहीं जाएगा अपितु इसका एहसास भी कराया जाएगा। मंथन बैठक में तय किया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने महिला, गरीब, किसान एवं युवा को सशक्त बनाने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनका व्यापक स्तर पर प्रचार -प्रसार किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश सरकार के कार्यों को आम जनता के मध्य प्रभावी तरीके से रखा जाएगा। भाजपा अब समाज में प्रबुद्ध, पिछड़ा, दलित एवं युवा सम्मेलन करने के साथ ही सभी मिशन शक्ति केंद्रो पर भी सम्मेलनों का आयोजन करेगी। भाजपा नये युवा मतदाता व जेन -जी पर भी विशेष ध्यान देगी। देश में जेन -जी आंदोलन और सरकार के प्रति नाराजगी को दूर करने के लिए चिंतन किया गया इनकी नाराजगी दूर करने के लिए विशेष अभियान में तीव्रता लाई जाएगी। भाजपा अपने चुनावी अभियान में रक्षात्मक नहीं अपितु आक्रामक प्रचार की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। यूजीसी को लेकर उठ रहे विवाद के बीच पार्टी के संभावित नुकसान को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह संदेश पहुंचाया जाएगा कि सरकार सभी वर्गों के सम्मान, सुरक्षा व हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। चिंतन शिविर में पार्टी व सरकार की अब तक की सभी नीतियों की व्यापक चर्चा की गई। चिंतन शिविर से सबसे बड़ी चर्चा यह रही है कि किन कमियों और अति आत्मविश्वास के कारण 2024 के लोकसभा चुनाव या कुछ उपचुनावों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। उन सभी कमियों तथा नाराजगी को दूर करते हुए भाजपा संगठन ने 60 प्रतिशत हमारा है और 40 प्रतिशत में बंटवारा है तथा उसमें भी हमारी हिस्सेदारी के संकल्प से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। आगामी माह से भाजपा जनआशीर्वाद यात्राएं निकालने वाली है। इनका समापन राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के साथ होगा। भाजपा सरकार ने हिंदुत्व तथा सनातन की धार को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 की अवकाश सूची में मकर संक्रांति, संत रविदास जयंती और महर्षि वाल्मीकि जयंती का अवकाश बढ़ा दिया है।

अभिव्यक्ति पर अंकुश और कला का अस्तित्व



महेन्द्र तिवारी
साहित्यकार एवं लेखक
पूर्व वायुसैनिक नई दिल्ली

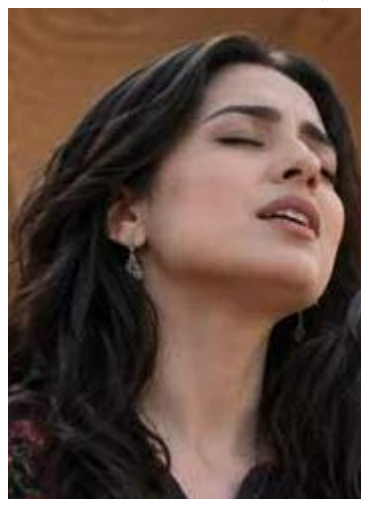
संगीत मानव सभ्यता की सबसे कोमल और सार्वभौमिक अभिव्यक्ति है, जो किसी भी सीमा, भाषा या विचारधारा से परे सीधे हृदय तक पहुँचती है। लेकिन जब किसी राज्य की व्यवस्था एक स्त्री के गायन को अपराध की श्रेणी में रख दे और उसके बदले शरीर पर कोड़े बरसाए जाएँ, तो यह केवल एक कानूनी कार्यवाही नहीं रह जाती, बल्कि समूची मानवीय संवेदना के समक्ष एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर देती है। ईरान के क़ुम शहर में 23 नवंबर 2026 को जो कुछ घटा, उसने विश्व भर के कलाप्रेमियों और चिंतकों को भीतर तक झकझोर दिया है। प्रसिद्ध ईरानी गायिका परस्तू अहमदी और उनके चार साथियों को चौहत्तर-चौहत्तर कोड़ों की सजा दी गई। उनके अधिवक्ता मुस्तफ़ा नीली द्वारा पुष्टि की गई इस सजा में केवल शारीरिक दंड ही शामिल नहीं है, बल्कि उन्हें दो वर्षों तक किसी भी कलात्मक गतिविधि में भाग लेने और देश से बाहर यात्रा करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इस पूरे प्रकरण की जड़ें दिसंबर 2024 की एक शांत और कलात्मक प्रस्तुति में छिपी हैं। परस्तू अहमदी ने ईरान के क़ुम प्रांत में स्थित ऐतिहासिक देर-ए-गचिन कारवाँसराय को अपनी संगीत संध्या के लिए चुना था। प्राचीन व्यापारिक मार्गों का साक्षी रहा यह कारवाँसराय ईरान की समृद्ध स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। वहाँ न तो कोई भीड़ थी और न ही कोई प्रत्यक्ष दर्शक। केवल कुछ वाद्ययंत्र, पुरुष संगीतकार, अभिलेखन के उपकरण और काले परिधान में खुले बालों के साथ गीत गाती परस्तू थीं। इसे एक काल्पनिक संगीत सभा के रूप में रचा गया था और इसका चलचित्र आभासी संसार के माध्यम से दुनिया के सामने रखा गया। देखते ही देखते यह प्रस्तुति लाखों लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई, किंतु यही लोकप्रियता कलाकारों के लिए संकट का कारण बन गई।

वर्ष 1997 में ईरान के नौशहर में जन्मी परस्तू अहमदी ने चलचित्र निर्देशन की विधिवत शिक्षा प्राप्त की है और उनका गहरा जुड़ाव पारंपरिक ईरानी संगीत से रहा है। यह पहली बार नहीं था जब उनकी कला को प्रशासनिक अवरोधों का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी ईरान में चले महिला, जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी सांगीतिक गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों ने आपत्तियाँ जताई थीं। ऐसे में कारवाँसराय की प्रस्तुति को किसी आकस्मिक घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह एक संवेदनशील कलाकार की निरंतर चल रही रचनात्मक यात्रा का ही स्वाभाविक विस्तार था, जिसमें वह अपनी मिट्टी के संगीत को नए संदर्भ में जीवित करना चाहती थीं।

प्रस्तुति के प्रसारित होते ही ईरान की न्यायिक व्यवस्था सक्रिय हो गई और कलाकारों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। परस्तू तथा उनके कुछ सहयोगियों को प्रारंभ में हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा किया गया। जून 2026 में क़ुम के न्यायालय ने गायिका और उनके साथियों को सार्वजनिक शालीनता भंग करने तथा आभासी मंच पर अनुचित सामग्री प्रसारित करने का दोषी ठहराया। सितंबर में उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर में दंड का क्रियान्वयन हुआ। इस सजा का सामना करने वालों में परस्तू के साथ संगीतकार सोहेल फ़कीह नसीरी, अमीन ताहेरी, अमीरअली पिरनिया और कार्यक्रम के आयोजक मोहसिन लश्करी शामिल हैं। यद्यपि प्रारंभिक प्रकरण में अन्य नाम भी जुड़े थे, परंतु दंड दिए जाने की पुष्टि इन्हीं पाँच लोगों के संबंध में हुई।

इस घटनाक्रम की गहराई को समझने के लिए ईरान की सामाजिक और वैधानिक पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालना आवश्यक है। वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति के पश्चात वहाँ सार्वजनिक जीवन में धार्मिक नियमों को कानूनी रूप दे दिया गया। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सिर ढकना अनिवार्य किया गया और उनके एकल



सार्वजनिक गायन पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। परस्तू की प्रस्तुति ने इन दोनों निर्धारित व्यवस्थाओं के सामने एक शांत किंतु स्पष्ट चुनौती प्रस्तुत की। उन्होंने न तो सिर ढका था और न ही अपने स्वर को चारदीवारी तक सीमित रखा।

यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म और आवश्यक अंतर को समझना होगा। किसी धार्मिक परंपरा को स्वेच्छा से स्वीकार करना और राज्य द्वारा बलपूर्वक उसे थोपना दो सर्वथा भिन्न बातें हैं। विश्व के विभिन्न हिस्सों में करोड़ों महिलाएँ अपनी व्यक्तिगत आस्था और विश्वास के कारण सिर ढकती हैं, वहीं असंख्य महिलाएँ ऐसा नहीं करतीं। एक सभ्य समाज का दायित्व है कि वह दोनों ही स्थितियों में स्त्री की स्वतंत्र इच्छा और उसकी गरिमा का सम्मान करे। किसी भी मनुष्य के वस्त्र उसकी नैतिकता, चरित्र या नागरिक अधिकारों का पैमाना नहीं हो सकते।

ईरान में स्त्रियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यह विमर्श वर्ष 2022 में तब अत्यंत तीव्र हो गया था, जब बाईस वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। पहनावे के नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप में हुई उस घटना ने पूरे देश में व्यापक जनआक्रोश को जन्म दिया। इसके बाद अनेक ईरानी महिलाओं ने अनिवार्य परिधान नियमों के विरुद्ध अपना मौन और मुखर प्रतिरोध दर्ज कराया। परस्तू का गायन इसी व्यापक सामाजिक चेतना से जुड़ता दिखाई देता है, फिर भी उनकी कला को केवल राजनीतिक विरोध के चश्मे से देखना उसके सौंदर्य के साथ अन्याय होगा। संगीत का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जो मनुष्य की स्मृतियों, प्रेम, पीड़ा और आशाओं को अभिव्यक्त करता है। ऐतिहासिक सराय की दीवारों के बीच गूँजा परस्तू का स्वर ईरानी संस्कृति की उसी पुरानी परंपरा में एक नया और सजीव अध्याय जोड़ रहा था।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठनों ने कोड़े मारने की इस सजा को क्रूर और अमानवीय बताया है। वैश्विक मानवाधिकार सिद्धांतों में शारीरिक यातना और अपमानजनक दंड के लिए कोई स्थान नहीं है। यद्यपि ईरानी प्रशासन पश्चिमी देशों की आलोचनाओं को दोहरे मापदंड कहकर नकारता रहा है, परंतु किसी नागरिक की शारीरिक गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न भू-राजनीतिक बहसों से कहीं बड़ा है।

यहीं पर कानून और न्याय के मूलभूत अंतर पर विचार करना प्रासंगिक हो जाता है। कानून किसी सत्ता द्वारा निर्मित नियमों का ढाँचा है, जबकि न्याय एक जीवंत नैतिक कसौटी है जो समय के साथ उन नियमों के औचित्य को परखती है। इतिहास साक्षी है कि अनेक ऐसे व्यवहार जिन्हें कभी कानूनन अपराध माना जाता था, मानवीय चेतना के विकास के साथ उन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया। अतः किसी दमनकारी नियम पर प्रश्न उठाना किसी देश या उसकी प्राचीन संस्कृति का अपमान नहीं, बल्कि उसके मानवीय भविष्य के प्रति चिंता का प्रमाण है।

परस्तू और उनके साथियों को मिला दंड केवल चौहत्तर कोड़ों की शारीरिक पीड़ा तक सीमित नहीं है। दो वर्षों तक कला से वंचित रहना किसी कलाकार की आजीविका और उसकी रचनात्मक पहचान पर सीधा आघात है। देश छोड़ने पर रोक उसके भविष्य के मार्ग अवरुद्ध करती है। यह स्थिति इस बात पर गंभीर चिंतन की माँग करती है कि राज्य की शक्ति की सीमा किसी व्यक्ति के निजी जीवन, उसके पेशे और उसकी सृजनात्मकता पर कहाँ जाकर रुकनी चाहिए।

इस पूरे प्रसंग पर विचार करते हुए हमें ईरानी समाज को किसी एक संकीर्ण खाँचे में बाँधने की भूल नहीं करनी चाहिए। वहाँ परंपरावादी और आधुनिक, दोनों तरह की विचारधाराओं को मानने वाले लोग बसते हैं। किसी सरकार के कठोर निर्णयों के लिए उस देश की समस्त जनता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। परस्तू के पक्ष में ईरान के भीतर से ही उठने वाले समर्थन के स्वर इस बात का प्रमाण हैं कि वहाँ का समाज भीतर से कितना विविध और संवेदनशील है।

भारत जैसे बहुलतावादी देश के नागरिकों के लिए भी इस घटना में गहरा संदेश छिपा है। हमारी शक्ति हमारी भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक विविधता में निहित है। यह प्रसंग हमें आत्ममंथन का अवसर देता है कि कहीं हम भी अपने आसपास किसी के पहनावे, विचार या कलात्मक अभिव्यक्ति के प्रति असहिष्णु तो नहीं हो रहे हैं। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी बात कहने का अधिकार नहीं, बल्कि असहमत स्वर को भी सम्मानपूर्वक सुनने का धैर्य है।

सत्ता के बल पर किसी कलाकार के मंच को तोड़ा जा सकता है, उसके वाद्ययंत्रों को खामोश किया जा सकता है और उसके शरीर को यातना दी जा सकती है। लेकिन जो गीत एक बार श्रोताओं के अंतर्मन में उतर जाता है, उसे किसी भी कोड़े से मिटाया नहीं जा सकता। परस्तू अहमदी का स्वर अब उस पुरानी सराय की सीमाओं को लाँघकर विश्व भर में मानवीय गरिमा का प्रतीक बन चुका है। किसी भी सभ्यता की वास्तविक उन्नति का मापदंड उसकी भौतिक समृद्धि या सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि यह है कि वह अपने समाज में निडर होकर गीत गाने वाली एक स्त्री के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करती है।

महिलाओं की भय-हिंसा मुक्ति से ही विकसित भारत संभव

ललित गर्ग

महिला हिंसा केवल किसी एक महिला के साथ हुआ अपराध नहीं है, यह पूरी मानवता की चेतना पर लगा हुआ घाव है। किसी महिला का घर में अपमानित होना, दहेज के लिए प्रताड़ित होना, कार्यस्थल पर उत्पीड़न सहना, सड़क पर असुरक्षित महसूस करना, यौन हिंसा का शिकार होना या डिजिटल माध्यमों से उसकी निजता और गरिमा को चोट पहुंचाना-इनमें से हर घटना समाज की उस मानसिकता को उजागर करती है, जिसमें स्त्री को बराबरी का मनुष्य मानने की भावना अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस इसलिए केवल स्मरण का दिन नहीं, बल्कि आत्ममंथन और सामाजिक संकल्प का दिन है। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाला 16 दिवसीय अभियान हमें यह याद दिलाता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्त करना केवल कानून और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह परिवार, समाज, पुरुष, संस्थाओं, न्याय-व्यवस्था और प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र की 2026 की थीम-महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए एकजुट हों, न्याय सुनिश्चित करें, पीड़ितों की सुरक्षा करें, और दोषियों को सजा से बचने न दें-का मूल संदेश स्पष्ट है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों एवं हिंसा पर नियंत्रण हो, न्याय सुनिश्चित हो, पीड़ितों की सुरक्षा हो और अपराधियों को दंड से बचने की संस्कृति समाप्त हो। सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर ही नारी-मुक्ति का वास्तविक रास्ता है, इसी से विकसित भारत संभव है।

आज दुनिया ने महिला हिंसा के अनेक पुराने चेहरों को पहचान लिया है, लेकिन हिंसा ने भी अपना स्वरूप बदल लिया है। घरेलू हिंसा, दहेज, बाल विवाह, यौन शोषण और बलात्कार के साथ अब साइबर उत्पीड़न, ऑनलाइन धमकी, निजी तस्वीरों का दुरुपयोग, डिजिटल निगरानी और कार्यस्थल पर मानसिक दबाव जैसी नई चुनौतियां सामने हैं। इसलिए महिला सुरक्षा की लड़ाई केवल पुलिस थाने तक सीमित नहीं रह सकती। उसे घर की मानसिकता, विद्यालय की शिक्षा, कार्यस्थल की संस्कृति और डिजिटल व्यवहार तक ले जाना होगा। भारत में स्थिति जटिल भी है और परिवर्तनशील भी। एक ओर महिलाएं राजनीति, प्रशासन, विज्ञान, शिक्षा, सेना, खेल, उद्योग और उद्यमिता में नई ऊंचाइयां छू रही हैं, दूसरी ओर अनेक महिलाएं आज भी हिंसा, भेदभाव, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक दबाव के घेरे में हैं। कानूनों की कमी से अधिक समस्या कई बार उनके प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक चुप्पी और पीड़िता को ही दोषी मानने वाली मानसिकता की होती है। महिला को यह समझाना आवश्यक है कि उसके साथ हुई हिंसा उसकी गलती नहीं है। अपराधी का अपराध अपराधी का ही है, पीड़िता को अपराधबोध में जीने के लिए मजबूर करना दूसरी हिंसा है। मीटू जैसे आंदोलनों और निर्भया कांड के बाद हुए कानूनी सुधारों ने समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव पैदा किया है। पहले जिस हिंसा को 'घर की बात ', 'इज्जत का मामला' या 'समझौते से सुलझाने' की सलाह देकर दबा दिया जाता था, उसके विरुद्ध आवाज उठाने का साहस बढ़ा है। लेकिन आवाज उठाना पहला कदम है, अंतिम समाधान नहीं। शिकायत करने वाली महिला को सुरक्षा, सम्मान, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक सहयोग और त्वरित न्याय मिले, तभी कानून पर उसका विश्वास मजबूत होगा। हमें यह भी समझना होगा कि हिंसा का वास्तविक अंत अदालत के फैसले से पहले मानसिकता के परिवर्तन से शुरू होता है। जिस घर में बेटे को अधिकार और बेटी को मर्यादा का पाठ अलग-अलग पढ़ाया जाता है, वहां समानता की नींव कमजोर रहती है। बेटे को यह सिखाना होगा कि स्त्री उसकी संपत्ति नहीं, स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उसकी सहमति सर्वोपरि है। प्रेम अधिकार नहीं, सम्मान है और पुरुषत्व का अर्थ प्रभुत्व नहीं, संवेदनशीलता है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी हिंसा के विरुद्ध एक प्रभावी कवच है। जो महिला शिक्षित है, आर्थिक रूप से सक्षम है, अपने अधिकारों से परिचित है और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त कर सकती है, उसके लिए हिंसक परिस्थितियों से बाहर निकलने की संभावना अधिक होती है। इसलिए भारत में 'पहुँच से सशक्तिकरण तक विकसित भारत के लिए आजीविका और समान अवसरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना' जैसी सोच अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड इकनोमिक फोरम कि स्थिति बताती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो महिलाएँ लगभग बराबरी के स्तर तक पहुँच गई हैं, परंतु आर्थिक अवसरों और राजनीतिक नेतृत्व में अभी भी उनकी भागीदारी सीमित है। वैश्विक स्तर पर महिलाएँ कुल कार्यबल का लगभग 42 प्रतिशत ही हैं और शीर्ष प्रबंधकीय पदों पर उनकी हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई के आसपास है। भारत में भी स्थिति मिश्रित है। विकसित भारत का सपना तभी सार्थक होगा, जब उसकी आधी आबादी भय से मुक्त होकर अपनी क्षमता के साथ आगे बढ़ सके। हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कैमरे, कानून और हेल्पलाइन नहीं, बल्कि सुरक्षित संस्कारों का वातावरण बनाना होगा। विद्यालयों में लैंगिक सम्मान और संवेदनशीलता की शिक्षा हो, परिवारों में बेटियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले, कार्यस्थलों पर शिकायत तंत्र निष्पक्ष और प्रभावी हो तथा पुलिस और न्याय-व्यवस्था पीड़िता के प्रति संवेदनशील बने। मीडिया और सोशल मीडिया को भी सनसनी के बजाय गरिमा और जिम्मेदारी का रास्ता चुनना होगा। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन पुरुष समाज में होना है। स्त्री के प्रति हिंसा की जड़ में केवल अपराधी प्रवृत्ति नहीं, बल्कि वह सोच भी है जो स्त्री को कमजोर, भोग की वस्तु या पुरुष के नियंत्रण का विषय समझती है। पुरुषत्व को प्रभुत्व से करुणा, अधिकार से उत्तरदायित्व और शक्ति से संरक्षण की ओर मोड़ना होगा। पुरुष यदि महिला की स्वतंत्रता को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं, उसकी मानवीय गरिमा का अधिकार समझेगा, तभी परिवर्तन स्थायी होगा। नये युग की समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, युद्ध, आतंकवाद, गरीबी और डिजिटल असमानता भी महिलाओं के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर रही हैं। यदि इन समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दशकों में करोड़ों महिलाएँ और लड़कियाँ अत्यधिक गरीबी की ओर धकेली जा सकती हैं। इतिहास के पन्ने यह भी बताते हैं कि जब-जब समाज संकट में पड़ा, तब-तब नारी शक्ति ने असाधारण साहस का परिचय दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उल्लेखनीय कदम उठाये हैं।

चाहे उज्ज्वला योजना के द्वारा उन्हें गैस सिलिंडर दिलाना हो, गावों में घरों और शौचालय का निर्माण हो या नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में पास कराना। आज दुनिया के सभी देश इस बात को मान रहे है की मोदी के नेतृत्व में भारत की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। खेल जगत से लेकर मनोरंजन जगत तक और राजनीति से लेकर सैन्य व रक्षा तक में महिलाएं बड़ी भूमिका में हैं। बात भारतीय या अभारतीय नारी की नहीं, बल्कि उसके प्रति दृष्टिकोण की है। आवश्यकता इस दृष्टिकोण को बदलने की है, जरूरत सम्पूर्ण विश्व में नारी के प्रति उपेक्षा एवं प्रताड़ना को समाप्त करने की है। इस दिवस की सार्थकता तभी है जब महिलाओं को विकास में सहभागी ही न बनाये बल्कि उनके अस्तित्व एवं अस्मिता को नौंचने की वीभत्सताओं एवं त्रासदियों पर विराम लगे, ऐसा वातावरण बनाये।

अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस हमें एक बड़ा संकल्प देता है-ऐसा समाज बनाने का, जहां महिला को अपनी सुरक्षा के लिए हर समय संघर्ष न करना पड़े, जहां बेटी को जन्म लेने से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक भय के बजाय सम्मान मिले, जहां न्याय पाने के लिए उसे अपनी पीड़ा बार-बार सिद्ध न करनी पड़े और जहां बलात्कार, दहेज-हिंसा, छेड़छाड़, उत्पीड़न और स्त्री-अस्मिता के अपमान जैसे शब्द धीरे-धीरे इतिहास के शब्दकोश का हिस्सा बन जाएं। महिला हिंसा का अंत केवल महिलाओं को सुरक्षित करने का अभियान नहीं है, यह पुरुषों को अधिक मानवीय और समाज को अधिक सभ्य बनाने का अभियान है। जिस दिन किसी महिला को अपनी गरिमा बचाने के लिए आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि समाज स्वयं उसकी गरिमा का प्रहरी बन जाएगा, उस दिन इस दिवस की सार्थकता पूरी होगी। नारी को दया नहीं, न्याय चाहिए। संरक्षण मात्र नहीं, समान अवसर चाहिए। सहानुभूति नहीं, सम्मान चाहिए। क्योंकि जिस समाज में उसकी आधी आबादी भयमुक्त नहीं है, वह समाज वास्तव में विकसित नहीं हो सकता।

लोकतंत्र का प्रहरी या सत्ता के सामने मौन होता मीडिया ?

- डॉ. प्रियंका सौरभ

लोकतंत्र की असली परीक्षा इस बात से नहीं होती कि सत्ता कितनी मजबूत है, बल्कि इस बात से होती है कि सत्ता से सवाल पूछने वाले कितने सुरक्षित हैं। जिस देश में पत्रकार सरकार की नीतियों, प्रशासनिक विफलताओं, भ्रष्टाचार और जनविरोधी फैसलों पर खुलकर सवाल पूछ सके, वहां लोकतंत्र जीवंत रहता है। लेकिन जिस व्यवस्था में सवाल पूछने वालों को ही संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगे, आलोचना को दुश्मनी समझा जाए और असहमति को अपराध की तरह प्रस्तुत किया जाए, वहां लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती पर चिंता स्वाभाविक है। प्रेस की स्वतंत्रता केवल पत्रकारों का अधिकार नहीं, बल्कि जनता का जानने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ङ्ख) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान इसी लोकतांत्रिक चेतना का आधार है। सर्वोच्च न्यायालय ने रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) और इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ (1985) जैसे मामलों में प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति के अधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। यह अधिकार सत्ता की कृपा से मिलने वाला उपहार नहीं, बल्कि लोकतंत्र में नागरिकों की संवैधानिक गरिमा का हिस्सा है।

पत्रकारिता का दायित्व केवल घटनाओं का विवरण देना नहीं, बल्कि उन घटनाओं के पीछे छिपे सच को सामने लाना भी है। सरकारी योजनाओं की सफलता का प्रचार करना आसान है, लेकिन उन योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति, प्रशासनिक उदासीनता और जनता की पीड़ा उजागर करना साहस मांगता है। जब पत्रकार किसी घोटाले की पड़ताल करता है, किसी अधिकारी की जवाबदेही तय करता है, किसी पीड़ित की आवाज सत्ता तक पहुंचाता है या किसी नीतिगत निर्णय के परिणामों पर प्रश्न उठाता है, तब वह लोकतंत्र की रक्षा करता है। लेकिन यदि मीडिया सत्ता की उपलब्धियों का मंच बनकर रह जाए और उसकी विफलताओं पर मौन धारण कर ले, तो पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है। लोकतंत्र में सत्ता को प्रश्नों से असुविधा हो सकती है, लेकिन प्रश्नों से असुविधा होना और प्रश्नों को दबाना दो अलग-अलग बातें हैं।

आज मीडिया के सामने सबसे बड़ा संकट केवल पत्रकारों की सुरक्षा का नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता का भी है। पत्रकारों पर दबाव अनेक रूपों में आता है। कभी विज्ञापन बंद करने की धमकी, कभी मुकदमों का भय, कभी सरकारी पहुंच से वंचित करना, कभी संस्थागत दबाव और कभी सीधे हिंसा के माध्यम से उनकी आवाज दबाने की कोशिश होती है। स्वतंत्र पत्रकारों के लिए यह संकट और गहरा है, क्योंकि उनके पीछे बड़े मीडिया संस्थानों की कानूनी टीम, आर्थिक संसाधन और संस्थागत सुरक्षा नहीं होती। एक फ्रीलांसर या स्थानीय पत्रकार किसी खबर की पड़ताल करते समय जितना जोखिम उठाता है, उसके बदले उसे अक्सर उतना आर्थिक और सामाजिक संरक्षण भी नहीं मिलता। पत्रकारिता का साहस पुरस्कारों और प्रशस्तियों से नहीं, बल्कि उस जोखिम से मापा जाता है जो सच सामने लाने के लिए उठाया जाता है।

पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा इस संकट का सबसे भयावह रूप है। गौरी लंकेश की 2017 में हत्या ने देश को झकझोर दिया था और यह प्रश्न छोड़ दिया था कि असहमति व्यक्त करने वाले पत्रकार आखिर कितने सुरक्षित हैं। किसी पत्रकार की हत्या केवल एक व्यक्ति की आवाज समाप्त नहीं करती, बल्कि समाज में भय का वातावरण पैदा करती है। जब एक पत्रकार पर हमला होता है, तो उसके साथ कई दूसरे पत्रकार भी अपनी खबरों, अपने शब्दों और अपने सवालों पर विचार करने लगते हैं। हिंसा का वास्तविक उद्देश्य केवल पीड़ित को चुप कराना नहीं, बल्कि उन सभी लोगों को भयभीत करना होता है जो सच लिखने का साहस रखते हैं। इस भय से पैदा होने वाली आत्म-सेंसरशिप किसी भी प्रत्यक्ष प्रतिबंध से अधिक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसमें पत्रकार स्वयं अपनी कलम रोकने लगता है।

डिजिटल युग ने पत्रकारिता को नई शक्ति दी है, लेकिन इसी डिजिटल दुनिया ने पत्रकारों के लिए उत्पीड़न का नया मैदान भी तैयार किया है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, धमकियां, चरित्रहनन, निजी जानकारी सार्वजनिक करना और संगठित ऑनलाइन हमले विशेषकर महिला पत्रकारों को निशाना बनाते हैं। किसी खबर से असहमति होना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन पत्रकार के परिवार, निजी जीवन और चरित्र पर हमला करना आलोचना नहीं, बल्कि उसे डराने की रणनीति है। जब किसी महिला पत्रकार को उसके विचारों के बजाय उसकी पहचान, व्यक्तिगत जीवन या लिंग के आधार पर अपमानित किया जाता है, तो यह केवल व्यक्तिगत उत्पीड़न नहीं, बल्कि सार्वजनिक संवाद को दूषित करने का प्रयास होता है। ऐसी परिस्थितियों में पत्रकारों का पीछे हटना केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं, समाज के सूचना अधिकार का नुकसान है।

डिजिटल निगरानी भी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। पत्रकारों के फोन, डिजिटल उपकरणों और संचार माध्यमों की निगरानी की आशंकाएं स्रोतों की गोपनीयता को खतरे में डालती हैं। खोजी पत्रकारिता में सूचना देने वाले व्यक्ति कई बार भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितताओं या संवेदनशील मामलों से जुड़े तथ्य सामने लाते हैं। यदि उन्हें यह भय हो कि उनकी पहचान उजागर हो सकती है, तो वे सामने आने से बचेंगे। परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण खबरें सार्वजनिक होने से पहले ही दम तोड़ सकती हैं। पेगासस से जुड़ा विवाद और 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर गठित जांच व्यवस्था ने निगरानी, निजता और पत्रकारिता की स्वतंत्रता के प्रश्न को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। स्रोतों की सुरक्षा पत्रकारिता की तकनीकी आवश्यकता ही नहीं, लोकतांत्रिक विश्वास की बुनियादी शर्त है।

इंटरनेट बंद करना, डिजिटल सामग्री पर प्रतिबंध लगाना और सूचना के प्रवाह को बाधित करना भी पत्रकारिता की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट प्रतिबंधों की समीक्षा और आनुपातिकता के सिद्धांत पर बल दिया। डिजिटल माध्यम आज समाचार संकलन, प्रसारण, संवाद और जनसंपर्क का प्रमुख साधन है। इंटरनेट बाधित होने पर केवल नागरिकों की अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं होती, बल्कि पत्रकारों की रिपोर्टिंग, समाचारों की पहुंच और सार्वजनिक विमर्श भी बाधित होते हैं। सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर प्रतिबंधों का औचित्य हो सकता है, लेकिन उनका अनिश्चितकालीन, व्यापक और अपारदर्शी उपयोग लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर कर सकता है।

इसके अतिरिक्त डिजिटल पत्रकारिता आर्थिक संकट से भी जूझ रही है। विज्ञापन का बड़ा हिस्सा तकनीकी प्लेटफॉर्मों के पास जा रहा है, जबकि समाचार संस्थानों की आय घट रही है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम तय करते हैं कि कौन-सी खबर अधिक लोगों तक पहुंचेगी और कौन-सी खबर दृश्यता से बाहर रह जाएगी। सनसनीखेज सामग्री, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और विवाद अक्सर गंभीर पत्रकारिता से अधिक प्रसारित होते हैं। इस व्यवस्था में पत्रकार के सामने दोहरा संकट है–एक ओर विश्वसनीय खबर तैयार करने का दायित्व, दूसरी ओर डिजिटल प्रतिस्पर्धा में टिके रहने का दबाव। जब पत्रकारिता की आर्थिक स्वतंत्रता कमजोर होती है, तो संपादकीय स्वतंत्रता पर भी खतरा बढ़ता है। विज्ञापनदाता, राजनीतिक हित और प्लेटफॉर्मों की प्राथम

संविधान और कानून के सामने सभी नागरिक एक समान : अनिल विज

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि संविधान और कानून के लिए सभी लोग एक समान है और एक समान कानून होना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जब भी यूनिवर्सल सिविल कोड लाएगी तो मैं इसका पुरजोर समर्थन करूंगा। विज आज चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों द्वारा यूनिफार्म सिविल कोड को हरियाणा में लागू करने के लिए पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए देश के सभी नागरिक एक समान होने चाहिए, जोकि संविधान की मूल भावना में भी है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सरकार और नागरिक का रिश्ता है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।



आज हरियाणा विधानसभा द्वारा संविधान समर्पित विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है जबकि विपक्षी दल कांग्रेस पंचकूला में संविधान बचाओ मार्च निकाल रहे है, के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि संविधान को जितनी बार इन्होंने (कांग्रेस) घायल किया है, उतनी बार किसी ने नहीं किया।

उन्होंने कहा कि 90 बार कांग्रेस ने धारा 356 लगाकर विधिवत चुनी हुई सरकारों को भंग करने का काम किया है। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर, सारे विपक्ष को जेलों में डालकर, सेंसरशिप लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। अब ये (विपक्ष कांग्रेस) केवल उन ज़ख्मों को छिपाने के लिए लाल किताब लेकर घूमते है।

कांग्रेस द्वारा संविधान को बचाने की बात की जा रही है, के बारे में पूछे हुए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि संविधान तो बहुत मजबूत है और बचा हुआ है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे प्रावधान किए है कि संविधान बचा रहे। उन्होंने कहा कि जब इन्होंने संविधान को तोड़ने की कोशिश की थी और इनके जो किए हुए गलत काम थे और संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई थी तथा संविधान संशोधन कर बदलाव किए थे, को जनता पार्टी की सरकार ने रद्द कर दिया था। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के मार्च के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक कलाबाजी है वह खाते रहे, हमें इससे क्या लेना।

हरियाणा विधानसभा में शोक प्रस्ताव पारित, पूर्व विधायकों एवं प्रदेश के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के आज यहां आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान विधानसभा के गत सत्र से अब तक दिवंगत हुए प्रमुख व्यक्तियों, हरियाणा के शहीदों तथा सदन के सदस्यों के परिजनों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक प्रस्ताव पारित किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़े और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने भी शोक प्रस्ताव पढ़े और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के विधायक आदित्य देवीलाल ने भी अपने-अपने दलों की ओर से शोक प्रस्ताव पढ़े और दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने विधायक पूजा के ससुर तथा हरियाणा के पूर्व मंत्री फूल चंद मुलाना के 20 नवंबर, 2026 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सदन ने हरियाणा विधानसभा के पूर्व



सदस्य सतविन्द्र सिंह के 21 नवंबर, 2026 को हुए दुःखद निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया।

सदन ने प्रदेश के उन 24 वीर सैनिकों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इन शहीदों में निरीक्षक सैन प्रकाश, झज्जर; निरीक्षक मनोज कुमार, गांव गोद, जिला महेंद्रगढ़; उप निरीक्षक राजकुमार, गांव कुतानी, जिला झज्जर; उप निरीक्षक विनोद कुमार, गांव भूषण कलां, जिला महेंद्रगढ़; उप निरीक्षक जगदीश चंद्र, गांव सोरखी, जिला हांसी; उप निरीक्षक वेदपाल, गांव मय्यड़, जिला हिसार; सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव रामबास, जिला महेंद्रगढ़; सहायक उप निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह, गांव फरमाना बादशाहपुर, जिला रोहतक; हवलदार सुरेश कुमार, गांव सुन्दरह, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार मंदीप कुमार, गांव गुमड़, जिला सोनीपत; हवलदार संदीप कुमार, गांव शेखपुरा, जिला सोनीपत; हवलदार विकास देशवाल, गांव मतलौडा, जिला पानीपत; हवलदार रणदीप सिंह, गांव मानहेरु, जिला भिवानी; हवलदार नरेश कुमार, गांव शादीपुर, जिला जींद; हवलदार अमित कुमार, गांव सिहोर, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार वेदप्रकाश, गांव कंवाली, जिला रेवाड़ी; नायक शेर सिंह, गांव बुढ़नपुर बांगर, जिला करनाल; नायक बलजिंद्र सिंह, गांव किरमारा, जिला हिसार; लांस नायक कृष्ण, गांव नंदगढ़, जिला जींद; लांस नायक सुखचैन सिंह, गांव कुत्ताबड, जिला सिरसा; सिपाही विकास कुमार, गांव ढाणी किरावड़, जिला भिवानी; सिपाही परवीन कुमार, गांव सीहा, जिला पलवल; सिपाही दिनेश वशिष्ठ, गांव हीरापुर, जिला फरीदाबाद तथा सिपाही सोमबीर सिंह, गांव अहरी, जिला झज्जर शामिल हैं।

सदन ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले इन वीर सैनिकों की शहादत को शत्-शत् नमन किया। इसके अलावा, सदन ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौसी शांति देवी तथा विधायक रणधीर पनिहार की बुआ मरमण देवी के दुःखद निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया। सदन ने दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की तथा परमात्मा से उन्हें इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। सदन के सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट का मौन भी रखा।

सीएम नायब सैनी पंजाब में झूठे दावे करने की बजाय हरियाणा में बढ़ते अपराधों को संभाले-दिग्विजय चौटाला

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने हरियाणा की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि भाजपा राज में प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने कहा कि रोहतक में ढाबे पर चार युवकों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर देना प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था का बेहद चिंताजनक ताजा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आए दिन गैंगवार, लूटपाट, फिरौती और व्यापारियों को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। प्रदेश में बदमाशों का राज है, व्यापारी और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। दिग्विजय चौटाला ने सवाल करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में जाकर नशे और गैंगस्टरवाद पर बड़े-बड़े दावे करते है, लेकिन अपने ही प्रदेश हरियाणा में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर उनकी चुप्पी क्यों है? उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उसी प्रदेश को असुरक्षा के माहौल में छोड़कर राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहना कहां तक उचित है ? दिग्विजय ने कहा कि सीएम नायब सैनी रोजाना पंजाब में जाकर झूठे दावे करने की बजाय हरियाणा की बिगड़ी कानून व्यवस्था को संभाले। दिग्विजय ने ये भी कहा कि भाजपा राजनीति दल नहीं बल्कि अमर बेल है यह जिसके साथ लगती है उसको सुखा देती है। देश और प्रदेश को बर्बाद करके उसे सुखाने का काम भाजपा सरकार रही है इसलिए देश की जनता को भाजपा से जल्द छुटकारा पाना होगा, नहीं तो यह देश को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगी।



हरियाणा के रोहतक में गैंगवार, चार लोगों की गोली मारकर हत्या

अनप्लग इंडिया

रोहतक। हरियाणा के रोहतक जिले में खरावड़ गांव के पास एक ढाबे पर बुधवार देर रात संदिग्ध गैंगवार के दौरान चार युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पांच हथियारबंद हमलावर एक कार में आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। यह अपराध पुलिस स्टेशन के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि गोलीबारी के बाद हमलावर कुछ मिनटों तक हथियारों को लहराते हुए घटनास्थल पर ही घूमते रहे और फिर वहां से भाग गए। यह घटना मिलन ढाबे पर हुई, जहां पीड़ित खाना खा रहे थे, तभी हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर ग्राहकों में अफरा-तफरी मच गई। वे अपनी जान बचाने के लिए मेजों और कुर्सियों के पीछे छिप गए।

गोलीबारी के कारण रेस्तरां में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। ग्राहक घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए मेजों और कुर्सियों के पीछे छिप गए। अपराधियों ने 50 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाईं।

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, तीन पीड़ितों की मौत डाइनिंग टेबल पर बैठे-बैठे ही हो गई जबकि चौथे पीड़ित का हमलावरों ने पीछा किया और भागने की कोशिश के दौरान उसे गोली मार दी।

मृतकों की पहचान रिंकू, विनीत, गंजू और हिमांशु के रूप में हुई है। इनमें से पहले तीन झज्जर जिले के दिघल गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं जबकि हिमांशु बेरी का रहने वाला था।

घटना के बाद, रोहतक रेंज के आईजी हामिद अख्तर और पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (सीआईए), स्पेशल सेल और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीमों ने भी घटनास्थल की जांच की और सबूत जुटाए।

जांचकर्ता इस मामले का संबंध 'भाऊ' और 'सनी रितोलिया' गिरोहों के बीच चल रही आपसी रंजिश से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, हमले के पीछे का मकसद और हमलावरों की पहचान अभी तक आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाई है।

पुलिस उपाधीक्षक ऋषिकांत ने मीडिया को बताया कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और पहचान की प्रक्रिया चल रही है। यह गैंगवार है या नहीं, यह जांच का विषय है। हमने मामले की जांच के लिए कई टीमें तैनात की हैं और उम्मीद है कि जल्द ही कुछ अहम सुराग मिल जाएंगे।

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और फरार हमलावरों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं।

गुरुग्राम में एयर रेड और भवन ढहने की स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस ने की मॉक ड्रिल

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। आपातकालीन परिस्थितियों में विभिन्न विभागों की तैयारियों, आपसी समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया को परखने के उद्देश्य से आज जिला परिषद परिसर, गुरुग्राम में सिविल डिफेंस की ओर से एयर रेड एवं भवन ढहने की स्थिति पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी, भवन के हिस्से के ढहने, आग लगने, धुआं फैलने और लोगों के फंसे होने जैसी परिस्थितियों का अभ्यास किया गया। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, होमगार्ड, एनसीसी, आपदा मित्र और सिविल डिफेंस के जवानों एवं स्वयंसेवकों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल के दौरान एयर रेड सायरन बजाकर अलर्ट जारी किया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद भवन के प्रभावित हिस्से में बचाव अभियान शुरू किया गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास घेराबंदी कर यातायात एवं कानून व्यवस्था संभाली, जबकि अग्निशमन विभाग ने आग बुझाने और बचाव कार्य में सहयोग किया। एसडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया। दो लोगों को आरसीसी स्लैब के नीचे से निकालने का अभ्यास किया गया, जबकि अन्य घायलों को विभिन्न मानव बचाव तकनीकों, स्ट्रेचर और फायरमैन लिफ्ट के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पहली मंजिल पर फंसे दो स्वयंसेवकों को रस्सी और चेयर नॉट तकनीक से नीचे उतारने का प्रदर्शन भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल सहायता केंद्र स्थापित कर घायलों की प्राथमिक जांच, श्रेणीवार पहचान (ट्रायेज), प्राथमिक उपचार और एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। ड्रिल में 14 घायल, 8 गंभीर घायल और 2 मृतकों की स्थिति दर्शाई गई। गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाने, मृतकों को पुलिस की प्रक्रिया के तहत सौंपने, बिजली आपूर्ति बंद करने तथा बचाव कार्य के बाद सुरक्षा जांच कर बिजली बहाल करने की प्रक्रिया भी प्रदर्शित की गई। दोपहर 12 बजे ड्रिल समाप्त होने के बाद सभी विभागों ने अपने अनुभव एवं सुझाव साझा किए और आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर प्रतिक्रिया, संचार, समन्वय तथा बचाव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की। ड्रिल में सिविल डिफेंस की डिप्टी कंट्रोलर सृष्टि, पुलिस टीम से हवलदार संजीव एवं अमरजीत, एसडीआरएफ टीम से उप निरीक्षक कपिल, अग्निशमन विभाग से अग्रणी अग्निशमन कर्मी राजेश कुमार, होमगार्ड टीम से जिला कमांडेंट अशोक कुमार एवं प्लाटून कमांडर विशाल धनखड़, एनसीसी से हवलदार सुंदर सिंह एवं हवलदार अमित कुमार, स्वास्थ्य विभाग से ईएमटी संदीप नेहरा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से परियोजना अधिकारी पूनम दहिया तथा सिविल डिफेंस प्रशिक्षक धीरज सहित विभिन्न विभागों के कर्मियों एवं स्वयंसेवकों ने भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला: महज 23 साल की उम्र में टीना ने बनाए दो ब्रांड

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में बनाए गए हरियाणा पवेलियन में इस बार 23 वर्षीय युवा उद्यमी टीना जैन का स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इतनी कम उम्र में दो ब्रांड खड़े कर चुकीं टीना जैन अपने स्टॉल पर मसाले और गुड़-चना प्रदर्शित कर रही हैं। मेले में आने वाले लोगों से उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने एक युवा उद्यमी के रूप में पहचान बनाई है। टीना जैन ने बताया कि करीब तीन साल पहले, जब वे 20 वर्ष की थीं, तब उनके मन में ब्रांड बनाने का विचार आया। उस समय उनके पिता मूंगफली ट्रेडिंग का काम करते थे। इसी पृष्ठभूमि के बीच परिवार में अपना ब्रांड लाने का विचार आया। तब उन्होंने मसाले, मूंगफली और गुड़ चने जैसे उत्पादों को ध्यान में रखकर ब्रांड की शुरूआत की। इसी सोच के साथ उन्होंने एफएसएससी (स्नस्ष्ट) वर्जन-6 लीड ऑडिटर का कोर्स किया और फूड सेफ्टी की बारीकियों को समझा। उन्होंने बताया कि इस पढ़ाई के बाद उन्हें साफ समझ आया कि पैकेट पर छपे लेबल और भीतर मौजूद उत्पाद के बीच काफी अंतर होता है। इसी अंतर को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया।

पापा ने हर कदम पर साथ दिया-टीना जैन ने बताया कि उनके पिता ने इस सफर में पूरा सहयोग किया। उनके सहयोग से उन्होंने ग्रोसरी ब्रांड 'फैमिली च्वाइस' की शुरुआत की। इसके बाद करीब एक महीने पहले उन्होंने रोस्टेड स्नैक्स का नया ब्रांड 'भुना' लॉन्च किया। टीना जैन के अनुसार भुना की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसके स्नैक्स वास्तव में रोस्टेड हैं, केवल दावे तक सीमित नहीं। उन्होंने बताया कि ट्रेड फेयर में प्रदर्शनी के दौरान उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उनके स्टॉल पर आने वाले लोग उत्पादों की गुणवत्ता को समझ रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं और बाजार में उपलब्ध अन्य उत्पादों तथा उनके उत्पादों के बीच का अंतर भी महसूस कर रहे हैं। अपनी सूझबूझ, सीखने की लगन और परिवार के सहयोग से टीना जैन ने यह साबित किया है कि उम्र नहीं, बल्कि सोच और मेहनत किसी भी उद्यम की नींव होती है। हरियाणा पवेलियन में उनका स्टॉल प्रदेश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का उदाहरण बनकर उभरा है।

आईटीआई गुरुग्राम में 30 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने और उन्हें औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने के उद्देश्य से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), गुरुग्राम में 30 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। संस्थान परिसर में आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में देश की प्रतिष्ठित औद्योगिक एवं तकनीकी कंपनियां भाग लेंगी। इनमें हीरो मोटोकॉर्प, मुंजाल शोवा, वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, रीजन स्टोर्स, क्लाउड स्काई इंफो विजन, आरआर पार्कौन, रामसन बिल्डटेक, श्याम इंडसपावर सॉल्यूशंस और एटीएमए ऑटोटेक इंजीनियर सहित अन्य कंपनियां शामिल होंगी। मेले में 10वीं, 12वीं, आईटीआई (कोपा, प्लंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीएमसी, फिटर, टर्नर) तथा स्नातक पास अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। कंपनियों द्वारा अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा। संस्थान के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में उत्पादन, मशीन ऑपरेशन, तकनीकी कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस, असेंबली, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन, अकाउंट्स, सेल्स सहित तकनीकी एवं गैर-तकनीकी क्षेत्रों में भर्ती की जाएगी। आईटीआई पास युवाओं को उनके संबंधित ट्रेड के अनुसार तकनीकी एवं औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे, जबकि 10वीं एवं 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए ऑपरेटर और प्रोडक्शन सहित अन्य पदों पर अवसर उपलब्ध होंगे। स्नातक पास युवा तकनीकी, प्रबंधन, कंप्यूटर एवं प्रशासन से संबंधित पदों के लिए साक्षात्कार में भाग ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उद्योगों और तकनीकी संस्थानों के बीच समन्वय को मजबूत करना है।

लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह ने जिला बार के लिए खोला खजाना, 30 लाख रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा

अनप्लग इंडिया

भिवानी। लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह ने आज जिला बार कार्यालय पहुंचकर अधिवक्ताओं से मुलाकात की और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ विभिन्न विषयों पर विस्तार से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जिला बार के विकास कार्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए अतिरिक्त 30 लाख रुपये देने की घोषणा की। सांसद इससे पहले भी अपनी संसद निधि से जिला बार एसोसिएशन के विकास के लिए 20 लाख रुपये अलॉट कर चुके हैं। सांसद की इस घोषणा से जिला बार में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज की न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है और जिला बार के विकास के लिए वे हमेशा सहयोग करते रहेंगे। बार की बेहतरी और आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। जिला बार कार्यालय पहुंचने पर सांसद धर्मबीर सिंह ने न्यायलय के नवनिर्मित 'न्याय द्वार' गेट नंबर-1



का विशेष रूप से अवलोकन किया। उन्होंने बार परिसर में किए गए इस निर्माण कार्य को देखा और बार प्रधान द्वारा कराए गए कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने बार के विकास और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों की सराहना करते हुए अपना सहयोग जारी रखने का भरोसा दिया। इससे बार परिसर में विकास एवं आवश्यक सुविधाओं के विस्तार को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं। सांसद धर्मबीर सिंह ने अधिवक्ताओं से मुलाकात के दौरान बार के विकास के प्रति अपनी सकारात्मक प्रतिबद्धता व्यक्त की।

ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज रहे विशेष रूप से मौजूदः

इस अवसर पर लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह के साथ पेरिस इंटरनेशनल ओलम्पिक से शतरंज एशिया महाद्वीप के महासचिव ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने भी इस अवसर पर अधिवक्ताओं के साथ मुलाकात एवं संवाद में भाग लिया।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं की रही गरिमामयी उपस्थितिः

इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के प्रधान युधिष्ठिर वत्स के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सोहन लाल मक्कड़, अविनाश सरदाना, बी.बी. जैन, ब्रह्मानंद, कांति चन्द्र कौशिक, पेरिस इंटरनेशनल ओलम्पिक से शतरंज एशिया महाद्वीप के महासचिव ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज, बजरंग लाल शर्मा, अरविंद शर्मा, नीरज भारद्वाज, राजेश तंवर, मनमोहन भूरटाना, संजय सोनी, सुमित जांगड़ा, राजीव गौड़, सुरेश मेहता, शमशेर दहिया, राजेंद्र वर्मा, परमहंस चोपड़ा, केंद्र मनी, कुलदीप शर्मा, महेश भारद्वाज, श्रीकांत भारद्वाज, मनीष चौहान, रोशन लाल शर्मा सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।

हरियाणा लोक भवन में मनाया गया संविधान दिवस



अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़: हरियाणा लोक भवन में गुरुवार को संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत के संविधान में निहित आदर्शों, मूल्यों एवं सिद्धांतों के प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान लोक भवन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन के लिए हॉल में एकत्रित हुए। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने प्रस्तावना का वाचन किया तथा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके साथ इसका सामूहिक रूप से पाठ किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के मूलभूत आदर्शों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन संवैधानिक मूल्यों को अपने आचरण और कार्यशैली में आत्मसात करना चाहिए तथा नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्षता एवं न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने सभी से संविधान के आदर्शों एवं मूल्यों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री विजयकुमार भाविकट्टी, राज्यपाल के एडीसी श्री मोहित हांडा, स्क्वाड्रन लीडर पि. भरत सहित लोक भवन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

खेल प्रशासन की गुणवत्ता पर लगी मुहर, हरियाणा ओलंपिक संघ को मिला आईएसओ प्रमाणपत्र

अनप्लग इंडिया

पंचकूला। हरियाणा में खेलों के प्रशासन और संचालन की व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में हरियाणा ओलंपिक संघ ने अहम उपलब्धि हासिल की है। पंचकूला स्थित ओलंपिक भवन को आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

इस प्रमाणन की खास बात यह है कि इसका दायरा केवल कार्यालय के प्रशासनिक कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों के कल्याण, खेल विकास कार्यक्रमों, राज्य खेल संघों के साथ समन्वय, प्रतियोगिताओं के प्रबंधन और शिकायतों के निपटारे जैसी गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया गया है।

खेल प्रशासन से खिलाड़ी कल्याण तक का दायराः ट्रांस कॉन्टिनेंटल सर्टिफिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 21 अक्टूबर 2026 को जारी प्रमाणपत्र 20 अक्टूबर 2029 तक वैध रहेगा। प्रमाणपत्र के अनुसार, संघ की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन आईएसओ 9001:2015 के मानकों के आधार पर किया गया है। इसमें



खेल प्रशासन, राज्य खेल संघों को मान्यता देने और उनके साथ समन्वय स्थापित करने, खेल आयोजनों के संचालन तथा खेलों के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। प्रमाणन के दायरे में खेलों से जुड़े ज्ञान संसाधनों का विस्तार भी रखा गया है। इसके तहत स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, खेल अकादमियों और सामुदायिक केंद्रों में खेल पुस्तकालयों तथा खेल ज्ञान संसाधन केंद्रों की स्थापना और प्रोत्साहन को शामिल किया गया है। इसके अलावा खिलाड़ियों के कल्याण और खेल गतिविधियों से जुड़ी शिकायतों के निवारण की व्यवस्था भी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा है। प्रमाणपत्र के साथ निगरानी की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार 20 अक्टूबर 2027 से पहले पहला ऑडिट और 20 अक्टूबर 2028 से पहले दूसरा निगरानी ऑडिट कराया जाना है। इसका उद्देश्य निर्धारित प्रक्रियाओं और गुणवत्ता मानकों को लगातार बनाए रखना है।

गुणवत्ता आधारित व्यवस्था बनाना प्राथमिकता : मीनू बेनीवाल

हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जसविंदर सिंह मीनू बेनीवाल ने कहा कि खेलों का विकास केवल खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रतियोगिताओं के अवसर उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए मजबूत और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था भी जरूरी है। आईएसओ प्रमाणन संघ की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित, जवाबदेह और गुणवत्ता आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जरूरत ऐसी व्यवस्था विकसित करने की है, जिसमें खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलें, खेल संघों के बीच समन्वय मजबूत हो और खेल गतिविधियों का संचालन तय मानकों के अनुरूप हो। संघ का प्रयास रहेगा कि इस प्रमाणन के जरिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार किया जाए और प्रदेश के खिलाड़ियों को इसका सीधा लाभ मिले।

सरकारी संस्थानों में भी पहले से लागू हैं आईएसओ मानकः

हरियाणा में सरकारी कामकाज और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए पहले भी कई कार्यालयों और संस्थानों को आईएसओ प्रमाणन मिल चुका है। रोहतक के उपायुक्त कार्यालय को आईएसओ 9001:2008 प्रमाणपत्र मिला था, जबकि जींद के लघु सचिवालय को भी आईएसओ प्रमाणन दिया गया था। गुरुग्राम के जिला एमएसएमई केंद्र को जनवरी 2022 में आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र मिला। वहीं, पुलिस व्यवस्था में भी इस दिशा में पहल हुई।

जुलाई 2024 में गुरुग्राम का सुशांत लोक थाना आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन हासिल करने वाला हरियाणा का पहला पुलिस थाना बना। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मशीनरी परीक्षण केंद्र में भी आईएसओ गुणवत्ता मानकों से जुड़ी पहल की गई है।

इन उदाहरणों के बीच हरियाणा ओलंपिक संघ का प्रमाणन खेल प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। खास बात यह है कि इसके तहत संघ की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ खेल विकास, खिलाड़ियों के कल्याण और राज्य खेल संघों के समन्वय जैसी जिम्मेदारियों को भी गुणवत्ता प्रबंधन के दायरे में लाया गया है।

संक्षिप्त डायरी

प्रयागराज कमिश्नरेट के 74 पुलिस इंस्पेक्टरों का स्थानांतरण, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया फेरबदल

अनप्लग इंडिया

प्रयागराज। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने निरीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया है। प्रयागराज कमिश्नरेट में तैनात 74 निरीक्षकों को दूसरे कमिश्नरेट और जोन में स्थानांतरित किया गया है। यह कार्रवाई उन निरीक्षकों के संबंध में की गई है, जिन्होंने एक जनपद में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है या 31 मई 2027 तक पिछले चार वर्षों में तीन साल की अवधि पूरी कर लेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पुलिस महकमे में तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश मुख्यालय की ओर से 25 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत प्रयागराज कमिश्नरेट में तैनात 74 पुलिस इंस्पेक्टरों का दूसरे कमिश्नरेट और जोन में स्थानांतरण किया गया है। पुलिस स्थापना बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी आदेश में सभी संबंधित निरीक्षकों को वर्तमान तैनाती स्थल से तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के मुताबिक, चुनावी तैयारियों के तहत ऐसे निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है, जिन्होंने किसी एक जनपद में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है या 31 मई 2027 तक पिछले चार वर्षों के दौरान तीन वर्ष की अवधि पूरी कर लेंगे। जनपद और कमिश्नरेट स्तर पर उनका समायोजन नहीं हो पाने के चलते उन्हें दूसरे स्थानों पर भेजने का निर्णय लिया गया है। स्थानांतरण सूची में कुल 37 निरीक्षक शामिल हैं। इन्हें कानपुर नगर, वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ और गोरखपुर जोन समेत विभिन्न स्थानों पर भेजा गया है। आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्थानांतरित निरीक्षकों के नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद उनकी आमद की तारीख सहित इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को निर्देशित किया गया है कि सभी स्थानांतरित निरीक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त कर इसकी आख्या पुलिस मुख्यालय को भेजें। किसी निरीक्षक को कार्यमुक्त करने में प्रशासनिक या नीतिगत बाधा आने पर इसकी जानकारी भी तत्काल मुख्यालय को देनी होगी। इसी तरह सत्येन्द्र कुमार का स्थानान्तरण कमिश्नरेट प्रयागराज से कमिश्नरेट लखनऊ, रचना का कमिश्नरेट प्रयागराज से कमिश्नरेट गाजियाबाद, राकेश कुमार भारती का कमिश्नरेट प्रयागराज से कमिश्नरेट वाराणसी, सुनील कुमार का कमिश्नरेट प्रयागराज से कमिश्नरेट वाराणसी, सतीश कुमार का कमिश्नरेट प्रयागराज से कमिश्नरेट गाजियाबाद, अनूप सरोज का कमिश्नरेट प्रयागराज से कमिश्नरेट वाराणसी, अशोक कुमार का कमिश्नरेट प्रयागराज से कमिश्नरेट लखनऊ, अनिल कुमार का कमिश्नरेट प्रयागराज से कमिश्नरेट लखनऊ, ओम प्रकाश का कमिश्नरेट

ढाई माह से लापता बुजुर्ग का गन्ने के खेत में मिला कंकाल

अनप्लग इंडिया

अमरोहा। ढाई माह से अधिक समय से लापता बुजुर्ग का कंकाल बुधवार को गांव के ही एक किसान के गन्ने के खेत में पड़ा मिला। शव पूरी तरह कंकाल में तब्दील हो चुका था। मानव अवशेष करीब 12 फीट के दायरे में बिखरे हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि बुजुर्ग किसी जंगली जानवर का शिकार हुए होंगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अवशेष कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। क्षेत्र के गांव महमदी निवासी लाल सिंह (65) पिछले ढाई महीने से लापता थे। परिजनों ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद उनके बेटे महेश सिंह की ओर से थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। बुधवार को गांव के ही पुष्पेंद्र सिंह अपने गन्ने के खेत में फसल काटने पहुंचे। इसी दौरान उन्हें खेत में मानव शरीर के अवशेष पड़े दिखाई दिए। उन्होंने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी तो मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर लापता लाल सिंह के बेटे महेश सिंह भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों कुलविंद्र सिंह, अजयवीर और परवेंद्र के साथ खेत पर पहुंचे। कंकाल के पास मिले अंडरवियर और बनियान के साथ ही हड्डी में फंसी प्लेट के आधार पर परिजनों ने अवशेष की पहचान लाल सिंह के रूप में की। ग्रामीणों के बीच चर्चा रही कि बुजुर्ग किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए होंगे। हालांकि, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लंबे समय तक खेत में पड़े रहने के कारण शव पूरी तरह कंकाल में बदल चुका था। सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि खेत में मानव अवशेष मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। अवशेषों को अग्रिम कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

एक मीटर चौड़ा और दो मीटर गहरा गड्ढा मिलने से मचा हड़कंप, बैरिकेडिंग

अनप्लग इंडिया

बलिया। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर चांददियर पुलिस चौकी के पास फिर सड़क धंस गई। पुलिस ने यहां बैरिकेडिंग कर दी है। इससे पहले भी तीन बार सड़क धंस चुकी है। ऐसे में गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बलिया जिले में बैरिया-मांझी मार्ग पर निमार्णाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता फिर सवालों के घेरे में है। यादव नगर गांव के समीप चांददियर पुलिस चौकी से करीब 200 मीटर दूर बुधवार सुबह सड़क के बीचोंबीच करीब एक मीटर गोलाई और लगभग दो मीटर गहराई का गड्ढा हो गया। पुलिस ने तत्काल मौके पर बैरिकेडिंग करा दी और कार्यदायी संस्था को सूचना दी। दोपहर करीब तीन बजे गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दिया गया था। वहीं, सड़क पर फिर से गड्ढा होने पर ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। क्षेत्र निवासी अशोक सिंह, सेवानिवत्त प्रो. सुभाष सिंह, पूर्व प्रधान भरत यादव, दुर्ग विजय सिंह और अधिवक्ता रणधीर सिंह नन्हे आदि ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर लगातार सड़क धंसने से चिंता बढ़ गई है क्योंकि इसी स्थान पर 18 सितंबर 2024 को बाढ़ के पानी के तेज बहाव में करीब 60 मीटर सड़क बह गई थी। उस समय सड़क क्षतिग्रस्त होने से आसपास के गांवों की लगभग चार हजार आबादी प्रभावित हुई थी। अब उसी स्थान के आसपास ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर फिर से गड्ढा होने से हादसे की आशंका है। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का समुचित ध्यान नहीं रखा जा रहा है। चांददियर पुलिस चौकी के दीवान मनीष कुमार सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों की नजर गड्ढे पर पड़ी थी। उन्होंने तत्काल मौके पर बैरिकेडिंग कराकर आवागमन को नियंत्रित किया। पुलिस ने संबंधित विभाग को सूचना देकर सड़क की मरम्मत कराने की पहल की। चांददियर पुलिस चौकी से करीब 200 मीटर दूर एनएच-31 के बैरिया-मांझी मार्ग का लगभग 60 मीटर हिस्सा बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बह गया था।

जिलाधिकारी ने अवैध खनन करने वालों पर दिये सख्त कार्यवाही के निर्देश, जबकि लापरवाह अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की हिदायत

हमीरपुर (अनप्लग इंडिया) कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अशोक कुमार की अध्यक्षता में कर करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन, वन, खनन, विद्युत, स्टाम्प एवं पंजीयन, मंडी तथा राजस्व सहित विभिन्न विभागों की राजस्व प्राप्तियों एवं कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व वसूली करने वाले विभागों को प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को करेत्तर राजस्व से संबंधित विभागों के साथ नियमित समन्वय स्थापित करने तथा पाक्षिक समीक्षा करने



के निर्देश दिए। खनन विभाग की वसूली एवं निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्यों में शिथिलता तथा बैठक में अद्यतन आंकड़ों के बिना उपस्थित होने पर खनन निरीक्षक श्री उमाकांत के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि खनन गतिविधियों में किसी भी स्तर पर विभागीय मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जालौन एवं हमीरपुर जनपदों की अंतरजनपदीय सीमा से संबंधित शिकायतों के दृष्टिगत सीमांकन स्थलों पर बड़े सूचना बोर्ड लगाए जाएं। सभी उपजिलाधिकारियों एवं खान अधिकारी को अवैध खनन तथा पट्टाधारकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और मुख्यमंत्री स्तर अथवा मीडिया से प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को ओटीएस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने तथा राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वहीं वाणिज्य कर विभाग को ब्याज माफी योजना का लाभ अधिकाधिक व्यापारियों तक पहुंचाने और कर अपवंचन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया। भूमि के दाखिल-खारिज एवं नामांतरण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्लॉट अथवा पट्टे के रूप में क्रय की गई भूमि का विवरण ऑनलाइन प्राप्त होते ही संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ की जाए तथा निर्धारित 45 दिनों की समयसीमा में दाखिल-खारिज की कार्रवाई पूरी की जाए। स्टाम्प चोरी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के साथ ही न्यायालयीन पत्रावलियों को न्यायालय में सुरक्षित रखने, उसी दिन वाद दाखिल करने तथा 45 दिनों के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आमजन को गुमराह करने अथवा अवैध वसूली की शिकायतों पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार न होने पर एसडीएम सदर श्री अभिषेक कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने की चेतावनी भी दी। आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने शराब की दुकानों का निर्धारित समय पर संचालन, ओवररेटिंग पर प्रभावी रोक, अवैध शराब के विरुद्ध सतत निगरानी तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समयबद्ध राजस्व वसूली सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियमित समीक्षा एवं प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

हाईस्कूल छात्रा की कनपटी में लगी गोली, पिता बोले- उठाते समय चल गई लाइसेंसी पिस्टल,



अनप्लग इंडिया

कानपुर। घाटमपुर के जैतीपुर गांव में हाईस्कूल की छात्रा लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली कनपटी में लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन छात्रा को सीएचसी से हैलट रेफर किए जाने के बाद निजी अस्पताल ले गए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में घाटमपुर के जैतीपुर गांव में बुधवार शाम घर में रखी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलने से किशोरी घायल हो गई। परिजन उसे आनन फानन सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से उसे उसकी नाजुक हालत को देखते हुए हैलट रेफर कर दिया गया है। पिता का कहना है कि किशोरी पिस्टल उठाकर देख रही थी, तभी गोली चल गई। गांव निवासी उपेंद्र सीआरपीफ में झारखण्ड में तैनात हैं। वह छुट्टी में घर आए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिस्टल साफ करके रखी ही थी तभी हाई स्कूल की छात्रा बेटी अदिति सिंह उर्फ स्वीटी (15) स्कूल से घर आई थी। वह दूसरे काम में व्यस्त हो गए तभी अदिति पिस्टल उठाकर देखने लगी। इसी दौरान पिस्टल से गोली चल गई और उसकी कनपटी में लग गई। गोली चलने की आवाज सुनकर पर सभी लोग मौके पर पहुंचे।

माघ मेले में 10 फीसदी बढ़ेगी बिजली व्यवस्था, लगेंगी 27,500 एलईडी स्ट्रीट लाइटें

अनप्लग इंडिया

प्रयागराज। माघ मेला 2027 में श्रद्धालुओं को बेहतर और निर्बाध बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बार पिछले मेले के मुकाबले विद्युत व्यवस्था में करीब 10 फीसदी इजाफा किया जाएगा। मेला क्षेत्र में 29 सब-स्टेशन, 23,120 बिजली के पोल और 27,500 एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। माघ मेला 2027 में श्रद्धालुओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए पिछले मेले के मुकाबले इस बार विद्युत व्यवस्था में करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। मेला क्षेत्र में 29 सब-स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा 23,120 बिजली के पोल लगाए जाएंगे। वहीं, पूरे मेला क्षेत्र में 27,500 एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी संदीप कुमार ने माघ मेला



2027 के भूमि पूजन के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले मेले में 25 हजार एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं, जिन्हें इस बार बढ़ाकर 27,500 किया जा रहा है। इसी तरह बिजली आपूर्ति के लिए डीजी सेट की संख्या 28 से बढ़ाकर 32 कर दी गई है। शिविरों में बिजली कनेक्शन की संख्या भी पिछले मेले के 66,220 के मुकाबले करीब 10 हजार बढ़ाई जाएगी, ताकि सभी शिविरों तक पर्याप्त बिजली पहुंचाई जा सके। सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या भी 500 से बढ़ाकर 600 की जा रही है। बिजली जाने पर वैकल्पिक व्यवस्था से मिलेगी आपूर्ति एमडी ने बताया कि बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए फीडरों पर आरएमयू (रिंग मेन यूनिट) लगाए जाएंगे। इससे एक स्थान पर बिजली आपूर्ति बाधित होने पर दूसरे स्रोत से तत्काल बिजली बहाल की जा सकेगी। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट और आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए एमसीबी लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है। मेला क्षेत्र में बिजली संबंधी शिकायतों और सूचनाओं के लिए क्यूआर कोड की सुविधा भी रहेगी। इसे स्कैन करके श्रद्धालु बिजली विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और शिकायत दर्ज कराने के लिए संपर्क कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सभी कार्यों को दिसंबर के मध्य तक पूरा करने का प्रयास है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर दिसंबर के अंत तक का समय लग सकता है।

बॉलीवुड पार्टियों से जुड़ रहे मेफेड्रोन तस्करों के तार

अनप्लग इंडिया

कानपुर। जालौन में पकड़ी गई मेफेड्रोन फैक्टरी के तस्करों के तार मुंबई की बॉलीवुड पार्टियों से जुड़ने लगे हैं, जहां कानपुर के बाबूपुरवा निवासी शैलू बाबा उर्फ शालू द्वारा मास्टरमाइंड खैय्याम संग मिलकर ड्रग्स सप्लाई करने की बात सामने आई है। जालौन में मेफेड्रोन की फैक्टरी लगाने वाले तस्करों के तार बॉलीवुड की रंगीन पार्टियों से जुड़ रहे हैं। मंगलवार को पुलिस की जांच में सामने आया कि बाबूपुरवा निवासी शैलू बाबा उर्फ शालू मास्टरमाइंड खैय्याम के साथ मिलकर मुंबई में बॉलीवुड की पार्टियों में भी ड्रग की सप्लाई करता था। पांच साल पहले ऐसी ही एक पार्टी में मेफेड्रोन सप्लाई करने में उसे पकड़ा गया था। कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसकी पैरवी की जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। फिलहाल, कानपुर पुलिस शैलू को तलाश रही है। डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि इस बिंदु को भी जांच में शामिल किया जाएगा। मंगलवार को पुलिस ने हाजिद अली उर्फ साहिल, रेहान कुरैशी और

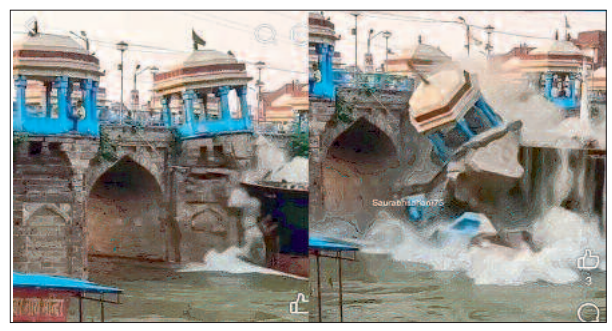


रिशम कुमार को पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक ये तीनों भी फैक्टरी के मास्टरमाइंड खैय्याम के लिए काम करते थे। इन तीनों से पूछताछ में बाबूपुरवा के ही शैलू बाबा उर्फ शालू, दानिश और हसीन के नाम सामने आए थे। ये लोग भी फैक्टरी से मेफेड्रोन लेकर उसे यूपी और मुंबई तक भेजने का काम करते थे। मंगलवार को शैलू का नाम सामने आते ही मुंशीपुरवा के इलाके में उसे लेकर बॉलीवुड कनेक्शन की चचाएं तेज हो गईं। चर्चा है कि एक पार्टी में ड्रग सप्लाई के मामले में फंसने के बाद जब वह जेल से छूटा, तो सीधे मुंशीपुरवा ही आया था। लोगों से कहता रहा कि प्रभावशाली व्यक्ति खान साहब ने ही उसे छुड़ाया था। चर्चा तो यह भी है कि पुलिस की एक टीम इस वक्त खैय्याम को पकड़ने के लिए मुंबई में डेरा डाले हुए है। इसके चलते मोहल्ले में रहने वाले कुछ और तस्कर इन दिनों वहां से भागकर कानपुर में छिपे हुए हैं। फिलहाल खैय्याम, रिजवान और शैलू का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि महाराष्ट्र के ही किसी एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। हालांकि अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बाबूपुरवा इलाके के लोगों का कहना है

जहाज की टक्कर से शाही पुल टूटने का एआई वीडियो वायरल, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर

अनप्लग इंडिया

वाराणसी। जौनपुर में शाही पुल को जहाज की टक्कर से टूटकर ढहते हुए एआई वीडियो वायरल हुआ। मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये वीडियो सौरभ सहानी नाम के फेसबुक पेज से प्रसारित किया गया था। ऐतिहासिक शाही पुल को पानी के बड़े जहाज की टक्कर से ढहते हुए दिखाने वाला एआई जनित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में संबंधित फेसबुक पेज का नाम सौरभ सहानी बताया गया है। क्या है मामला प्राथमिकी के अनुसार, 25 नवंबर को उपनिरीक्षक आलोक त्रिपाठी पुलिस बल के साथ कोतवाली क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सोशल



मीडिया की निगरानी और सूत्रों से जानकारी मिली कि सौरभ सहानी नाम के फेसबुक पेज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का दुरुपयोग कर जौनपुर के ऐतिहासिक शाही पुल का एक भ्रामक वीडियो तैयार कर वायरल किया गया है। वीडियो में पानी के बड़े जहाज को शाही पुल से टकराते और परिणामस्वरूप ऐतिहासिक पुल को ध्वस्त होकर गिरते हुए दिखाया गया है। तहरीर में वीडियो को पूरी तरह असत्य, भ्रामक और जनमानस में सनसनी व भय फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित बताया गया है। इससे आम जनता में भ्रम और भय की स्थिति उत्पन्न होने तथा ऐतिहासिक धरोहर की छवि धूमिल होने की आशंका जताई गई है। उपनिरीक्षक आलोक त्रिपाठी की तहरीर पर फेसबुक पेज सौरभ सहानी के अज्ञात संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक संतोष कुमार यादव को सौंपी गई है।

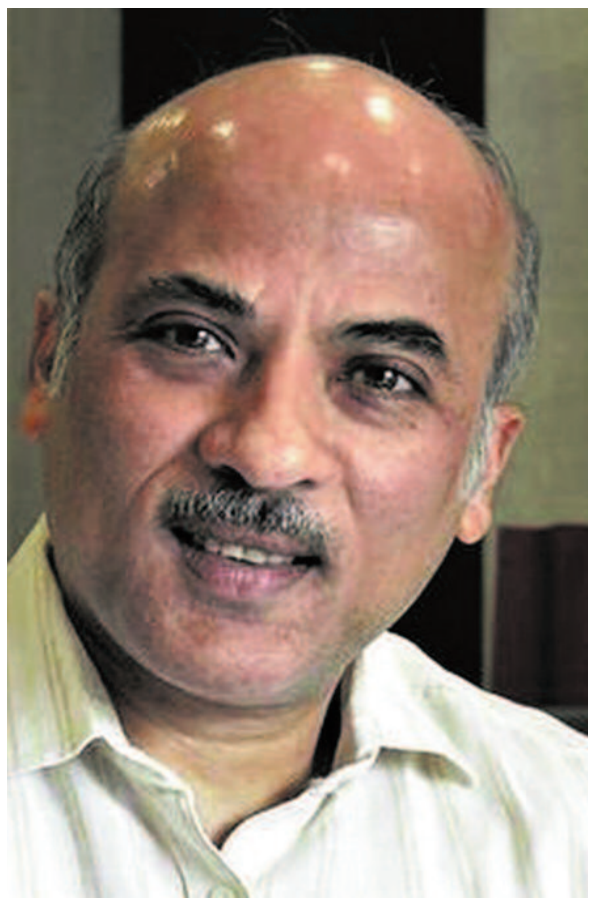
सड़क हादसे में सिपाही की मौत, सीपी और कमिश्नर ने पार्थिव शरीर को दिया कंधा

अनप्लग इंडिया

वाराणसी। वाराणसी में सिपाही महेश कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई। सहजन के पेड़ से बुलेट बाइक टकराने से उस पर सवार सिपाही की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस आयुक्त और मंडलायुक्त ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। सारनाथ रेलवे स्टेशन के पीछे मंगलवार रात सहजन के पेड़ से टकराकर बुलेट सवार पुलिसकर्मी महेश कुमार 25 वर्ष की मौत हो गई। बुधवार की सुबह सारनाथ पुलिस ने शव को संरक्षण में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिपाही



के अंतिम विदाई में पुलिस अफसरों की आंखें भी छलक गईं। अफसरों ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। आजमगढ़ के गढ़वल निवासी वर्षीय महेश कुमार वर्तमान में पुलिस लाइन में तैनात थे। रात लगभग एक बजे महेश अपनी बुलेट से फरीदपुर रिंगरोड से स्टेशन की ओर जा रहे थे। स्टेशन के पीछे उनकी बुलेट असंतुलित होकर सहजन के पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलमेट पहने होने के बावजूद महेश बुरी तरह घायल हो गए। रात में ही सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक अमरजीत कुमार उन्हें इलाज के लिए पंडित दीनदयाल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सारनाथ थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि महेश कुमार वर्ष 2018 बैच के पुलिसकर्मी थे। तीन भाई और दो बहनें हैं। वह अपने तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन राजेश कुमार पांडेय ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की भी बारीकी से जांच की। डीसीपी वरुणा राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि महेश पुलिस लाइन में तैनात थे और मंगलवार को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मंडलायुक्त की स्कॉर्ट ड्यूटी में थे पुलिस आयुक्त और मंडलायुक्त ने पार्थिव शरीर को दिया कंधा मंडलायुक्त के एस्कॉर्ट में तैनात कांस्टेबल महेश कुमार के निधन पर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और मंडलायुक्त विजयेंद्र पांडियन ने आरक्षी के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। इस दौरान पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पुलिस आयुक्त ने महेश कुमार के परिजनों से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने इस कठिन समय में परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि किसी सहकर्मी का असमय निधन पुलिस परिवार के लिए दुखद है। इस अवसर पर दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई।



सूरज ने परिवार की बदलती तस्वीर और फैमिली एंटरटेनमेंट के भविष्य पर बात की

निर्देशक सूरज बड़जात्या एक बार फिर पारिवारिक रिश्तों की नई परिभाषा लेकर आ रहे हैं। आयुष्मान खुराना और शरवरी स्टारर उनकी नई फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में परिवार, बदलती पीढ़ी की सोच और रिश्तों के बीच संतुलन जैसे मुद्दे दिखेंगे। सूरज ने परिवार की बदलती तस्वीर और फैमिली एंटरटेनमेंट के भविष्य पर खुलकर बात की...

आज की जेन जी परिवार से ज्यादा अपनी पहचान और पर्सनल स्पेस को महत्व देती है। आपकी फिल्म क्या कहती है?

यह बदलाव हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे समय में हम अपनी इच्छाएं माता-पिता के सामने नहीं रखते थे। उन्होंने जो कहा, वही किया। लेकिन आज के बच्चे अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं, सवाल करते हैं और फैसलों में भागीदारी चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह गलत नहीं है। माता-पिता के तौर पर हमें उनकी बात सुननी और समझनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार हमारा अनुभव ही सही हो। उनकी बातों के पीछे भी एक नजरिया और तर्क होता है। असल जरूरत दोनों पीढ़ियों के बीच संतुलन बनाने की है। समाज बदल रहा है तो हमारी फिल्मों को भी बदलना होगा। मेरी नई फिल्म इसी सोच पर आधारित है।

'ये प्रेम मोल लिया' में परिवार के किस पहलू को दिखाया है?

मैं इसे अपनी सबसे प्रोग्रेसिव फैमिली फिल्मों में से एक मानता हूं। इसका संदेश है कि माता पिता को बच्चों की प्राथमिकताओं का सम्मान करना चाहिए। मेरी 'हम आपके हैं कौन' में नजरिया था कि परिवार के साथ रहना कितना खूबसूरत होता है। सबका एक साथ होना मेरी ड्रीम वर्ल्ड का हिस्सा था। 'हम साथ-साथ हैं' में भी संदेश था कि बच्चों को सही संस्कार दें तो परिवार में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इस फिल्म में हम कहना चाहते हैं कि मायका और ससुराल दो अलग-अलग घर नहीं, बल्कि एक परिवार जैसे होने चाहिए।



आयुष्मान और शरवरी को कास्ट करने की क्या वजह रही

इस कहानी का विषय प्रोग्रेसिव है और आज की पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले मेरे दिमाग में आयुष्मान का नाम आया। उनकी फिल्मोग्राफी में ऐसे कई किरदार हैं, जो समाज की स्थापित धारणाओं को सहजता से चुनौती देते हैं। मुझे लगा कि वह इस कहानी को बिना किसी अतिरिक्त आक्रामकता के स्वाभाविक और रिलेटेबल बना पाएंगे। वहीं शरवरी मेरे लिए सरप्राइज पैकेज हैं। मैंने उनकी एक फिल्म में बॉक्सिंग का शॉट देखा था, जिसमें उनका समर्पण प्रभावित करने वाला था। मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी, जो अपने विचारों पर मजबूती से खड़ी हो सके। मुझे संदेह था कि इतनी कम उम्र में वह मैच्योर किरदार निभा पाएंगी या नहीं, लेकिन उन्होंने हर कदम पर सरप्राइज किया। उन्होंने किरदार और फिल्म की इंडियननेस को पूरी तरह अपनाया है।

ईयर एंडर 2026

टी20 विश्व कप का खिताब, छक्कों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए साल 2026 बेमिसाल रहा। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया अपनी ही धरती पर टी20 विश्व कप के खिताब का बचाव करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी। इसके साथ ही एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल के अलावा टीम ने छक्कों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। टी20 विश्व कप का खिताब : भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराने के साथ ही भारत टी20 विश्व कप के खिताब का बचाव करने वाला पहला देश बना। इसके साथ ही अपनी घरेलू सरजमीं पर टीम इंडिया चैंपियन बनने वाली पहली



टीम भी बनी। भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा और टीम को सिर्फ एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारत के लिए संजू सैमसन ने सर्वाधिक 321 रन बनाए जबकि 8 मैचों में 14 विकेट लेकर बेस्ट गेंदबाज रहे। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल : जापान की धरती पर खेले गए एशियन गेम्स 2026 में भी भारतीय क्रिकेट टीम का जलवा रहा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन ईशान किशन ने बनाए जबकि अक्षर पटेल सबसे सफल गेंदबाज रहे।

मुल्डर की शानदार गेंदबाजी, बांग्लादेशी बल्लेबाजों का दूसरी इनिंग में भी 'सरेंडर'

साउथ अफ्रीका ने एक पारी और 219 रनों से जीता दूसरा टेस्ट

सेंचुरियन(एजेंसी)। साउथ अफ्रीका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट मैच में एक पारी और 219 रनों से हराया। सुपरस्पोर्ट्स पार्क के मैदान पर बांग्लादेश के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दूसरी इनिंग में भी निराशाजनक रहा और पूरी टीम सिर्फ 184 रन बनाकर सिमट गई। दूसरी पारी में बांग्लादेश तंजीद हसन तमीम और महफिजुल इस्लाम ने सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़े। तंजीद 29 रन बनाकर आउट हुए, जबकि महफिजुल 38 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे। मोमिनुल हक अपना खाता भी नहीं



खोल सके। वहीं, कप्तान नजमुल हुसैन शांतो 34 रन बनाने के बाद वियान मुल्डर का शिकार बने। तौहीद हिरदॉय भी अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 33 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुए। लिटन दास ने 15 रन बनाए, जबकि जेकर अली 2 रन ही बना सके। शोरिफुल इस्लाम (0) और तस्कीन अहमद (10 रन) भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। खलील अहमद 5 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका की तरफ से वियान मुल्डर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 11 ओवर के स्पेल में 31 रन देकर 7 विकेट चटकाए, जबकि मार्को जानसेन ने 2 विकेट अपने नाम किए। कगिसो रबाडा ने एक विकेट झटका। बांग्लादेश की पूरी टीम पहली पारी में सिर्फ 91 रन बनाकर ढेर हो गई थी, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट खोकर 494 रन बनाने के बाद अपनी पारी को घोषित किया था।

न्यूजीलैंड-भारत दूसरा टेस्ट क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में कैसा है भारत का टेस्ट रिकॉर्ड, 2020 में करना पड़ा था करारी हार का सामना

क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट आज से



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाना है। वेलिंगटन में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। आइए आपको बताते हैं कैसा रहा है टीम इंडिया का हेगली ओवल के मैदान पर टेस्ट रिकॉर्ड। दरअसल, भारतीय टीम ने क्राइस्टचर्च के इस मैदान पर अब तक सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला था और इस मुकाबले में टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। 2020 में विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम पहली पारी में 242 रन बनाकर ऑलआउट हुई थी।

इसके जवाब में भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड की पहली पारी को 235 रनों पर समेटने में सफल रहे थे। दूसरी पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने आसानी से न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए थे और पूरी टीम महज 124 रन बनाकर सिमट गई थी। न्यूजीलैंड ने 132 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल करते हुए टेस्ट मैच को तीसरे ही दिन अपने नाम कर लिया था। हालांकि, शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इस बार पिछली हार का हिसाब चुकता करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। न्यूजीलैंड ने इस ग्राउंड पर अब तक कुल 15 टेस्ट मैच खेले हैं और टीम को 9 में जीत हासिल हुई है। हेगली ओवल में न्यूजीलैंड को 4 टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारतीय टीम के लिहाज से पहला टेस्ट मैच शानदार रहा था। भारत का बल्लेबाजी क्रम जबरदस्त फॉर्म में नजर आया था। केएल राहुल और ऋषभ पंत शतकीय पारियां खेलने में सफल रहे थे, तो यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल और कप्तान गिल ने भी अर्धशतकीय पारियां खेली थीं।

भारतीय टीम पहली पारी में ही 720 रन बनाने में सफल रही थी, जो न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर था। हालांकि, भारतीय टीम के गेंदबाज दूसरी पारी में संघर्ष करते हुए जरूर दिखाई दिए थे। टीम के गेंदबाज आखिरी दो सेशन में सिर्फ एक ही विकेट निकालने में सफल रहे थे और न्यूजीलैंड टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रहा था।

दो बार शून्य पर आउट हुए लाथम, बुमराह ने दोनों पारियों में किया था शिकार, क्या निकाल पाएंगे तोड़?

क्राइस्टचर्च (एजेंसी)। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह का सामना करना आसान नहीं है। भारत के तेज गेंदबाज ने सीरीज के पहले टेस्ट की दोनों पारियों में उन्हें खाता भी नहीं खोलने दिया था। इसके बावजूद लाथम दूसरे टेस्ट में अपनी बल्लेबाजी की शैली में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनकी तैयारी पिछले सप्ताह जैसी ही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट शुक्रवार से क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में खेला जाएगा। बुमराह की अनूठी गेंदबाजी शैली और बल्लेबाज के करीब गेंद डालने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। स्विंग के अनुकूल परिस्थितियों में उनका सामना करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।





अपनी बल्लेबाजी में बदलाव नहीं करना चाहते लाथम

लाथम अपनी बल्लेबाजी शैली पर ही कायम रहना चाहते हैं। उनका मानना है कि तकनीक में बदलाव करने के बजाय अपने विचारों में स्पष्टता रखना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा, 'कभी-कभी मुश्किल यह होती है कि अगर कुछ अलग करने की कोशिश सफल नहीं होती, तो इससे ध्यान भटक जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज मैं इस मुकाम पर हूं तो इसका कारण यही है कि मैं जो कर रहा हूं, उसे लेकर पूरी तरह स्पष्ट हूं।' लाथम ने कहा, 'तकनीक के मामले में इसे बिल्कुल सरल रखना सबसे महत्वपूर्ण है। चुनौती यह हो सकती है कि उस सोच से बाहर निकलकर रन बनाने का कोई जादुई तरीका खोजने की कोशिश की जाए। लेकिन हमारे खेल में ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं है।'

बुमराह की गेंदबाजी शैली को बताया चुनौतीपूर्ण

दूसरे टेस्ट की पूर्व संध्या पर लाथम ने बुमराह की गेंदबाजी पर बात की। उन्होंने कहा, 'जसप्रीत बुमराह निश्चित रूप से चुनौती पेश करते हैं, चाहे वह नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हों या पुरानी गेंद से। उनकी गेंदबाजी शैली अनूठी है और वह दूसरे गेंदबाजों की तुलना में गेंद को बल्लेबाज के थोड़ा अधिक करीब डालते हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उस गेंद को खेलने के लिए खुद को तैयार रखना है, जो सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। हो सकता है कि कुछ खिलाड़ियों का खेलने का तरीका मुझसे बिल्कुल अलग हो।'

नए श्रम कानून एक साल बाद भी कंपनियों में पूरी तरह से नहीं हुए लागू-रिपोर्ट

सर्वे का खुलासा- वेतन, पीएफ और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी से कंपनियों पर बढ़ेगा बोझ

नई दिल्ली ।

कर्मचारियों और मजदूरों की भलाई के लिए देश में बीते साल लागू किए गए चार नए श्रम कानूनों को कंपनियां पूरी तरह से अपनाने में अभी भी पीछे हैं। एक ताजा सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि एक साल बीत जाने के बाद भी आधी से अधिक कंपनियां इन नियमों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं, जिसका मुख्य कारण वेतन संरचना और पेरोल सिस्टम में आने वाले बदलाव हैं।

सर्वे के अनुसार केवल 50.6 फीसदी कंपनियों ने ही इन कानूनों को लागू करने की तैयारी पूरी की है, जबकि 28.8 फीसदी अभी इस प्रक्रिया में हैं। चिंताजनक बात यह है कि 11.7 फीसदी कंपनियों ने तो इस दिशा में काम ही शुरू नहीं किया है और 9 फीसदी को तो इन बदलावों की जानकारी तक नहीं है।

यानी, लगभग आधी कंपनियां अभी भी नए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने से दूर हैं। नए श्रम कानूनों से कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंका है। 74.4 फीसदी कंपनियों ने माना है कि नए वेतन नियमों से उनका खर्च बढ़ेगा, जिसमें से 49.6 फीसदी का अनुमान है कि यह खर्च 5 फीसदी तक बढ़ सकता है। ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में योगदान में वृद्धि को इसका मुख्य कारण बताया गया है।

भारतीय बैंकों की ऋण वृद्धि 2027 में भी दोहरे अंक में रहने का अनुमान-फिच

मार्च 2028 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2027-28 में भारतीय बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन स्थिर रहेगा

नई दिल्ली ।

विश्व की प्रमुख रे टिंग्स एजेंसी फिच ने गुरुवार को कहा कि भारतीय बैंकों की ऋण वृद्धि 2027 में भी दोहरे अंक में रहने की उम्मीद है। वहीं लागत दक्षता में सुधार से उनकी लाभप्रदता बढ़ेगी और पूंजी पर्याप्तता स्थिर बनी रहेगी। फिच को उम्मीद है कि मार्च 2028 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2027-28 में भारतीय बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन स्थिर रहेगा। मजबूत आर्थिक वृद्धि से ऋण वृद्धि करीब 15 प्रतिशत बनी रहेगी, जबकि नीतिगत ब्याज दर में मामूली बढ़ोतरी से शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) और आय को समर्थन मिलेगा। एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बैंकों पर जारी अपनी रिपोर्ट में फिच ने कहा कि कर्ज की अवधि बढ़ने के साथ परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कर्ज की वसूली और बट्टे खाते में डाले जाने वाले कर्ज से इसका असर कम हो जाएगा। ऋण वृद्धि और लागत दक्षता में सुधार से लाभप्रदता को समर्थन मिलेगा और पूंजी पर्याप्तता स्थिर बनी रहेगी। फिच के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में कुछ क्षेत्रों में कर्ज की तेज वृद्धि के कारण नए गैर-निष्पादित ऋण (एनपीएल) के मामले मामूली रूप से बढ़ सकते हैं। इनमें बिना गारंटी वाले व्यक्तिगत ऋण और कृषि कारोबार से जुड़े कर्ज शामिल हैं, जो बाहरी परिस्थितियों में बदलाव के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।

भारतीय चीनी को मिला अमेरिकी बाजार, 8,606 टन निर्यात को हरी झंडी

अमेरिका के संभावित शुल्क के बावजूद भारतीय निर्यातकों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली ।

भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अमेरिकी बाजार में 8,606 टन कच्ची चीनी के निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह निर्यात कोटा 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक की अवधि के लिए वैध होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा इस संबंध में जारी एक आदेश के अनुसार, यह निर्णय टैरिफ रेट कोटा (योजना के तहत लिया गया है, जो भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी लाभ दिलाएगा। टीआरक्यू योजना के तहत एक निश्चित मात्रा तक के सामान पर आयात शुल्क या तो शून्य होता है या काफी कम दर पर लगाया जाता है।

यह प्रावधान भारतीय चीनी को अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाएगा, खासकर ऐसे समय में जब कुछ राजनीतिक जानकारों के अनुसार अमेरिकी प्रशासन भारत सहित विभिन्न देशों पर फिर से आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। इसके बावजूद, यह कदम भारतीय चीनी को अमेरिकी बाजार में मिठास घोलने का अवसर देगा।

निर्धारित 8,606 टन की मात्रा मीट्रिक टन रॉ वैल्यू में तय की गई है, जो अंतरराष्ट्रीय चीनी व्यापार में कच्ची चीनी के वजन मापने का एक मानक है।

इस निर्यात के लिए मूल देश का प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन) अनिवार्य होगा, जिसे मुंबई स्थित विदेश व्यापार महानिदेशालय का अतिरिक्त महानिदेशक जारी करेगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। एपेडा ही संबंधित कंपनियों और निर्यात की मात्रा की सिफारिश करेगा, जिसके आधार पर आवश्यक दस्तावेज जारी किए जाएंगे।

संक्षिप्त समाचार

अमेरिका: न्यू ऑरलियन्स से फ्लोरिडा जा रहा विमान समंदर में गिरा, दो बच्चों समेत छह लापता; बचाव अभियान जारी

मिसिसिपी, एजेंसी। मिसिसिपी के तट के पास मंगलवार को एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद, बचाव दल छह लोगों की तलाश कर रहे हैं, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। 'सेसना 210' नाम का यह विमान मैक्सिको की खाड़ी में, मिसिसिपी के पास्कागौला और हॉर्न आइलैंड के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हॉर्न आइलैंड 'गल्फ आइलैंड्स नेशनल सीशोर' का हिस्सा है। कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता जुआन रॉस ने बताया कि बचाव दल को पानी में तैरती हुई तीन लाइफ जैकेट, एक लाइफ राफ्ट और विमान का केबिन मिला है, लेकिन विमान में सवार चार वयस्क और 8 व 10 साल के दो बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट 'फ्लाइटअवेयर' के अनुसार, यह सेसना विमान न्यू ऑरलियन्स से फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्स जा रहा था। इस दुर्घटना की जांच करने वाले 'फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन' और 'नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड' ने मंगलवार को बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी है। इस महीने की शुरुआत में, दक्षिण फ्लोरिडा में एक 'लियरजेट 60' बिजनेस जेट सीधे जमीन से टकरा गया था, जिसमें सवार सभी नौ लोगों की मौत हो गई थी। इस भयानक हादसे को कारों में बैठे लोगों ने अपने वीडियो में कैद कर लिया था।

अमेरिका में एच5एन1 से एक व्यक्ति की मौत- डब्ल्यूएचओ

वाशिंगटन, एजेंसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अमेरिका के वाशिंगटन में एच5एन1 वायरस से इंसानों के संक्रमित होने की पुष्टि की है। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि संगठन के मुताबिक आम जनता को इससे कोई खास खतरा नहीं है। ये मामले 16 अक्तूबर से 4 नवंबर के बीच सामने आए। इनमें से एक मौत का मामला भी है, जो संक्रमित डेयरी पशुओं या उनसे दूषित वातावरण के संपर्क में आने के बाद हुई पहली दर्ज मौत है। ये तीनों मामले वयस्कों के हैं, जो वॉशिंगटन राज्य की याकिमा काउंटी में डेयरी पशु फार्मों पर काम करते थे। इन फार्मों के डेयरी पशुओं में हाल ही में यह वायरस पाया गया था। वायरस के संपर्क में आए लोगों और उनके करीबी संपर्कों की जांच और निगरानी की जा रही है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि बर्ड फ्लू वायरस मुख्य रूप से जानवरों में फैलते हैं और इंसानों को बहुत कम संक्रमित करते हैं। हालांकि, संक्रमित जानवरों या दूषित वातावरण के संपर्क में आने पर इंसानों में भी कभी-कभार संक्रमण हो सकता है।

सोलोमन द्वीप ने ऑस्ट्रेलिया को बनाया अपना प्रमुख सुरक्षा साझेदार, चीन के लिए सैन्य अड्डे का रास्ता बंद

बीजिंग, एजेंसी। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच सोलोमन द्वीप ने ऑस्ट्रेलिया को अपना प्रमुख सुरक्षा साझेदार घोषित किया है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने बुधवार को एक नए द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में स्पष्ट किया गया है कि सोलोमन द्वीप में किसी भी विदेशी देश का सैन्य या सुरक्षा अड्डा नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मैथ्यू वेले ने संयुक्त बयान में समझौते की जानकारी दी। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब खबरें हैं कि सोलोमन द्वीप 2022 में चीन के साथ हुए पांच वर्षीय सुरक्षा समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगा। हालांकि, वेले ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ समझौते में गोपनीयता की शर्त है और दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है।

हांगकांग अग्निकांड के एक साल बाद भी पीड़ितों को नहीं मिला इंसाफ

हांगकांग , एजेंसी। हांगकांग में पिछले साल हुए भीषण अग्निकांड के एक साल बाद भी पीड़ित परिवार सदमे और न्याय की उम्मीद के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। 26 नवंबर 2025 को वांग फुक कोर्ट आवासीय परिसर की सात इमारतों में लगी आग में 168 लोगों की मौत हो गई थी। यह शहर में कई दशकों की सबसे भीषण आग की घटनाओं में से एक थी। जांच में सामने आया कि आग संभवत: जलती हुई सिगरेट से लगी और तेजी से फैलने वाले मचान के ज्वलनशील पदार्थों ने इसे भयानक रूप दे दिया। हादसे से पहले भी निवासियों ने निर्माण कार्य के दौरान आग से जुड़े खतरों की शिकायत की थी।

मोगा रैली: केजरीवाल ने मान के नाम पर मांगे वोट, कांग्रेस-बीजेपी पर साधा निशाना

मोगा, एजेंसी। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले, आम आदमी पार्टी (आप) ने मोगा में अपने स्थापना दिवस पर खुशहाल पंजाब-महारैली का आयोजन किया। इस दौरान आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नाम पर वोट मांगे और कांग्रेस व भाजपा दोनों पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री मान ने अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को कृषि सुधार कानूनों को वापस लाने की शर्त पर हुआ बताया।

केजरीवाल ने पंजाब के मतदाताओं को आगाह किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, तब मुफ्त बिजली और महिलाओं को मिलने वाले एक हजार रुपये प्रति माह जैसी योजनाएं बंद हो जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन्हें फ्री की रेवड़ी कहने का जिक्र कर कहा कि दिल्ली में भी केंद्र ने उनकी सरकारी स्कीमें बंद की थीं। उन्होंने लोगों से मान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की अपील की ताकि ये योजनाएं जारी रह सकें। एक हजार रुपये की योजना में देरी पर उन्होंने पिछली सरकारों पर खजाना खाली करने का आरोप लगाया। रैली के दौरान, केजरीवाल ने सीएम मान के साथ मिलकर नए लाभार्थियों को राशन कार्ड भी वितरित किए, जिसके तहत दस लाख नए लोगों को कार्ड दिए जा रहे हैं।

सीएम मान ने अपने संबोधन में कांग्रेस की आंतरिक कलह पर निशाना साधकर कहा कि वहां 6-7 मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं और उनमें रोज लड़ाई होती है। उन्होंने परगट सिंह के गोल करने के उदाहरण से कांग्रेस की आपसी खींचतान को उजागर किया। केजरीवाल ने अपनी सरकार की



उपलब्धियां गिनाकर दावा किया कि उन्होंने 77 हजार युवाओं को नौकरियां दी हैं और एक भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसने नौकरी के लिए पैसे दिए हैं। उन्होंने पिछली सरकारों में रिश्वतखोरी के तौर-तरीकों, जैसे अटैची तौलकर पैसे लेने का जिक्र किया।

आप के स्थापना दिवस पर केजरीवाल का संकल्प: न पार्टी डरेगी और न ही तय लक्ष्यों से पीछे हटेगी

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बधाई देकर देश के लिए बड़े संकल्प का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी न डरेगी और न ही अपने लक्ष्यों से पीछे हटेगी, क्योंकि देश के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी के अब तक के सफर पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे 2012 में पार्टी की स्थापना के समय कई सवाल उठे थे, कि क्या यह कुछ कर पाएगी, कितने दिन टिकेगी, और इन लोगों को राजनीति की क्या समझ है। हालांकि, केजरीवाल ने गर्व से कहा कि पार्टी न केवल टिकी रही, बल्कि उसने पूरे देश के लोगों का भरोसा और समर्थन भी जीता। उन्होंने पार्टी की सफलताओं का जिक्र कर कहा कि आप ने दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में अपनी सरकारें बनाई हैं। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर, गोवा और गुजरात सहित अन्य कई राज्यों में भी पार्टी को लोगों का विश्वास और प्यार मिला है। केजरीवाल ने जोर दिया कि आप ने काम की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत मुद्दों पर बात की, और यह राजनीति से प्रभावित नहीं हुई बल्कि उसने खुद राजनीति को बदल दिया। अपने संदेश में, उन्होंने भविष्य की योजनाओं और पार्टी के अटल निश्चय को दोहराया। केजरीवाल ने लिखा, अभी बहुत कुछ करना है। देश के लिए बहुत काम करना है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ भी दीं। गौरतलब है कि आप की स्थापना 26 नवंबर, 2012 को अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई थी। यह पार्टी 2011 में यूपीए सरकार के दौरान सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से निकली थी। केजरीवाल ने पार्टी शुरू करने के लिए 26 नवंबर की तारीख इसलिए चुनी, क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया था।

माकपा नेता के भड़काऊ भाषण की होगी पुलिस जांच: गृह मंत्री

पय्यान्नूर , एजेंसी। केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने घोषणा की कि पुलिस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता और पूर्व विधायक टी.आई. मधुसूदनन के भाषण की गहन जांच करेगी। मधुसूदनन ने सोशल मीडिया पर पार्टी की आलोचना करने वालों को खुलेआम चेतावनी दी थी कि पार्टी उनसे हिसाब चुकता करेगी और इसके गंभीर परिणाम भुगतना होगा। गृह मंत्री चेन्निथला ने कहा कि गृह विभाग इन टिप्पणियों को अत्यंत गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि रह चुके व्यक्ति के लिए इस तरह के धमकी भरे भाषण देना अनुचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य सरकार ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी और न ही पुलिस ऐसा होने देगी। पुलिस जांच के लिए भाषण का पूरा पाठ जुटा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के.मुरलीधरन ने भी मधुसूदनन के बयानों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केरलम की मौजूदा सरकार हिंसा की धमकी देने वाले भाषणों पर चुप नहीं बैठेगी और ऐसी हरकतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुरलीधरन ने चेतावनी दी कि जेन जी के दौर में इस तरह के भाषणों से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि यह वामपंथी पार्टी के पतन का कारण बन सकते है। स्वास्थ्य मंत्री मुरलीधरन ने माकपा नेताओं द्वारा हाल ही में आए सी.वी.धनराज हत्याकांड के फैसले पर सवाल उठाने और न्यायाधीशों पर टिप्पणी करने को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने अदालतों के सम्मान पर जोर देकर अरियिल शुकूर हत्याकांड का उदाहरण दिया, जहां कांग्रेस और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) भी फैसले से असंतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने न्यायाधीशों के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की। उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों ही मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से चूक हुई है। मधुसूदनन ने पय्यान्नूर में एक डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) कार्यक्रम में ये धमकी भरे बयान दिए थे, जो धनराज हत्याकांड के फैसले के बाद आयोजित किया गया था। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी की आलोचना करने वालों को चेताया था कि पार्टी उनसे हिसाब चुकता करेगी और पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि पार्टी का अपमान करने वालों को शायद पहले ही उनके किए की सजा मिल चुकी है और जो लोग लड़ाई को सड़कों पर ले जाएंगे, उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतना होगा। गृहमंत्री चेन्निथला ने कहा कि नेताओं और पूर्व विधायकों को अशांति भड़काने के बजाय शांति बनाए रखने तथा हत्याओं और हिंसा को रोकने के लिए काम करना चाहिए।

मंच से खरगे की इमरान मसूद को नसीहत... बातों से ज्यादा काम पर ध्यान केंद्रित करें

यूपी में गठबंधन की सरकार लानी है और मोदी-योगी को हराना

लखनऊ , एजेंसी । कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में पार्टी नेताओं को गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गठबंधन की सरकार लानी है और मोदी-योगी को हराना है, क्योंकि अंदरूनी झगड़े जीत को मुश्किल बनाते हैं।

कांग्रेस नेता खड़गे ने इस दौरान पार्टी नेता और सांसद इमरान मसूद के जोश की सराहना की, लेकिन साथ ही उन्हें गठबंधन धर्म निभाने और केवल बातों से ज्यादा काम पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर काम करना होगा तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव का जिक्र कर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दावा किया कि अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर ली थी और वह थोड़े से चूक गए,



नहीं तब मौजूदा प्रधानमंत्री गुजरात जाकर बैठते।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगेसंविधान बचाओ मार्च में शामिल होने लखनऊ पहुंचे थे, हालांकि लखनऊ प्रशासन ने मार्च की अनुमति नहीं दी थी। खड़गे के जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला, लेकिन पार्टी कार्यालय से करीब 150 मीटर आगे बढ़ने पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने पहले से ही थ्री-लेयर बैरिकेडिंग लगा रखी थी। लगभग 40 मिनट तक कांग्रेसियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद पुलिस ने मार्च में शामिल प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद सहित कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उन्हें इको गार्डन ले जाकर बाद में छोड़ दिया गया।

इस घटना पर प्रतिक्रिया देकर कांग्रेस नेता अजय राय ने योगी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस के दिन सरकार संविधान को कुचलने का काम कर रही है, जो दर्शाता है कि ये लोग संविधान को मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता संविधान बचाने के लिए सड़क पर उतरा है। कांग्रेस नेता राय ने ओवैसी और चंद्रशेखर की रैलियों को भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित बताया।

सौरव दास की विदेश यात्रा पर रोक: दिल्ली हाईकोर्ट में बोला केंद्र, उनके खिलाफ एलओसी जारी

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार 26 नवबंर को सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास की याचिका पर सुनवाई हुई, जिन्हें ब्रिटेन जाने से रोक दिया गया था। केंद्र ने दिल्ली की अदालत को बताया कि मुंबई पुलिस ने 23 नवंबर को उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था, इस कारण उन्हें विदेश जाने से रोका गया। सौरव दास को 24 नवंबर को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रिटेन जाना था, जहां उन्हें कॉकरोच मूवमेंट विषय पर बोलना था। अपनी याचिका में दास ने आरोप लगाया है कि 23 नवंबर की रात लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से ठीक पहले उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर रोक दिया गया था। इस रोक को उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

अमेरिका में खसरे का कहर: दो की मौत, इस साल 5838 मामले आए सामने

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में खसरे का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। दो राज्यों विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में खसरे से जुड़ी दो और मौतें दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही दोनों राज्यों में इस साल इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या क्रमशः तीन और नौ हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की है। विस्कॉन्सिन के स्वास्थ्य सेवा विभाग ने मंगलवार को बताया कि लाफायेट काउंटी में एक वयस्क की खसरे से जुड़ी दिक्कतों के चलते मौत हुई है। परिवार की निजता का सम्मान करते हुए मृतक के बारे में अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की गई। राज्य में इस साल अब तक खसरे के 920 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें शुक्रवार के बाद से सामने आए 88 नए मामले भी शामिल हैं। 918 मामले



अगस्त में शुरू हुए प्रकोप से जुड़े हैं। राज्य में इस साल 20 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है।

पेंसिल्वेनिया में कैसे बढ़ा संक्रमण : वहीं, पेंसिल्वेनिया के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को सेंटर काउंटी के एक ऐसे निवासी की मौत की पुष्टि की, जो खसरे से संक्रमित पाया गया था और जिसका टीकाकरण नहीं हुआ था। विभाग ने मृतक की उम्र या पहचान से जुड़ी अन्य जानकारी नहीं दी। पेंसिल्वेनिया में इस साल अब तक 46 काउंटियों में खसरे के 1,638 मामले दर्ज किए गए हैं। 18 नवंबर के बाद से 49 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमण के कारण 330 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इस साल खसरे से हुई नौ मौतें छह अलग-अलग काउंटियों में दर्ज की गई हैं। सेंटर काउंटी में यह पहली मौत है।

संक्रमण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए : पेंसिल्वेनिया में अप्रैल के अंत में संक्रमण फैलना शुरू होने के बाद से स्वास्थ्यकर्मियों ने 287 अस्थायी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से खसरा, मम्प्स और रूबेला (एमएमआर) के 7,400 से अधिक टीके लगाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि संक्रमण पर काबू पाने के लिए और टीकाकरण केंद्र खोले जाएंगे। देशभर में कितने मामले सामने आए? अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, 19 नवंबर तक देश में खसरे के 5,838 पुष्ट मामले दर्ज किए जा चुके थे। यह संख्या 2025 में पूरे साल दर्ज किए गए 2,289 मामलों से कहीं अधिक है। इस साल सामने आए कुल मामलों में करीब 96 प्रतिशत संक्रमण के प्रकोप से जुड़े हैं। हालांकि, सीडीसी के राष्ट्रीय आंकड़ों की गणना की अंतिम तारीख राज्यों की हालिया रिपोर्ट से पहले की है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य विभाग अपने यहां संक्रमण की सबसे ताजा स्थिति की जानकारी देते हैं। विस्कॉन्सिन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बुखार और शरीर पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई देने पर सीधे अस्पताल या क्लीनिक जाने के बजाय पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को फोन करें, ताकि दूसरे लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरती जा सकें।

प्रवासी परिवारों के आवास संबंधी नियम पर भड़के राज्य, ट्रंप सरकार पर केस

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिकी राज्यों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ आवास संबंधी एक नियम को लेकर मुकदमा दायर किया है। इस नियम के तहत उन परिवारों को मिलने वाली किराये की सहायता बंद हो सकती है, जिनके सदस्यों में अमेरिकी नागरिकों के साथ-साथ ऐसे आप्रवासी भी शामिल हैं जो संघीय सहायता पाने के योग्य नहीं हैं। सोमवार को मैसाचुसेट्स की एक संघीय अदालत में दायर मुकदमे में, 'आवास और शहरी विकास विभाग' (एचयूडी) की एक नीति को चुनौती दी गई है। यह नीति सार्वजनिक आवास, रेंटल वाउचर और अन्य सब्सिडी वाले आवास कार्यक्रमों को प्रभावित करती है। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स इस चुनौती का नेतृत्व कर रहे हैं। इनके साथ अन्य राज्य, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो भी शामिल हैं। वे अदालत से इस नियम को रद्द करने और इसे लागू होने से रोकने की मांग कर रहे हैं।

यह विवाद 'मिश्रित-स्थिति' वाले परिवारों से जुड़ा है – ऐसे परिवार जिनमें कुछ सदस्य संघीय आवास सहायता के लिए पात्र हैं, जबकि अन्य सदस्य अपने आव्रजन (इमिग्रेशन) दर्जे के कारण पात्र नहीं हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत, सरकार परिवार की सब्सिडी को केवल पात्र सदस्यों के हिस्से तक सीमित कर देती है। एक अपात्र रिश्तेदार परिवार के साथ रह तो सकता है, लेकिन उसे सब्सिडी का कोई हिस्सा नहीं मिलता। नया नियम इस व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इससे पात्र नागरिक और आप्रवासी लोग सहायता से



वंचित हो सकते हैं, क्योंकि वे किसी ऐसे रिश्तेदार के साथ रहते हैं जो इस सहायता के लिए पात्र नहीं है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने कहा, 'परिवारों को एक साथ रहने और सिर पर छत होने के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उनके कार्यालय का अनुमान है कि कैलिफोर्निया में 7,000 से अधिक ऐसे 'मिश्रित-स्थिति' वाले परिवार प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें अमेरिकी नागरिक बच्चे भी शामिल हैं। एचयूडी ने 12 नवंबर को अंतिम नियम जारी किया, जो 14 दिसंबर से लागू होगा। इसके तहत, इन आवास कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले या लाभ पाने वाले सभी लोगों को अपनी नागरिकता या पात्र आव्रजन दर्जे का सत्यापन (वेरिफिकेशन) कराना होगा, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो।

विभाग का कहना है कि ये बदलाव संघीय पात्रता शर्तों को लागू करते हैं और सीमित आवास संसाधनों को उन परिवारों तक पहुंचाते हैं, जिनके सभी सदस्य पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं। एचयूडी का अनुमान है कि इस नीति के जरिए सालाना 167 मिलियन से 218 मिलियन डॉलर की रेंटल सहायता उन परिवारों को मिल सकती है जो पूरी तरह से पात्र हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं।

अमेरिकी सैनिक चीन को सेना के सीक्रेट बेच रहा था:मिसाइल और रॉकेट सिस्टम तक की जानकारी दी

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी सैनिक पैसों के लिए अपने ही देश की सैन्य जानकारी चीन से जुड़े लोगों को बेच रहा था। वह सेना के सीक्रेट दस्तावेजों की तस्वीरें अपने मोबाइल से खींचता और उन्हें आगे पहुंचाता था। इन दस्तावेजों में मिसाइलों और रॉकेट सिस्टम से जुड़ी अहम जानकारियां थीं। सेना के सीसीटीवी कैमरों में उसकी यह हरकत रिकॉर्ड हो गई। अब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी का नाम जियान झाओ है। उसकी उम्र 37 साल है। वह वॉशिंगटन के जॉइंट बेस लुईस-मैककॉर्ड में तैनात था। सेना में रहते हुए उसे कई दस्तावेजों और सैन्य उपकरणों तक पहुंच मिली हुई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसने इसका गलत फायदा उठाया।

सीक्रेट बेचने के बदले हजारों डॉलर मिलते थे : झाओ अपने निजी मोबाइल से सेना के गोपनीय दस्तावेजों की तस्वीरें खींचता था। इनमें सेना के ऑपरेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सैन्य अभ्यास और रॉकेट-मिसाइल सिस्टम से जुड़ी जानकारी थी। उसने रॉकेट सिस्टम से जुड़ी तकनीकी किताबों के कुछ हिस्से भी चीन से जुड़े लोगों को दिए। इसके अलावा उसने सेना के कंप्यूटर और सरकारी हार्ड ड्राइव बेचने की पेशकश भी की थी। जांच के मुताबिक, इस काम के बदले उसे



हजारों डॉलर मिले।

पूर्व सैनिक भी साजिश में शामिल : अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक यह साजिश 2021 के आखिर में शुरू हुई थी। इसमें रूयो डुआन नाम का एक पूर्व अमेरिकी सैनिक भी शामिल था। वह ओरेगन में रहता था। डुआन ने झाओ और सेना में काम कर रहे दूसरे सैनिकों को गोपनीय जानकारी देने के लिए तैयार किया था। वह चीन से जुड़े लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने और सैनिकों को पैसे दिलाने का इंतजाम करता था। डुआन भी इस मामले में अपना जुर्म कबूल कर चुका है।

सीसीटीवी में तस्वीरें लेते दिखा, 17 लाख रुपए मिले जांच एजेंसियों ने सेना के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में झाओ को गोपनीय दस्तावेजों की तस्वीरें लेते देखा। इसके बाद 6 मार्च 2025 को उसे वॉशिंगटन के लेसी शहर में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। घर की तलाशी में करीब 30 हजार डॉलर यानी लगभग 27 लाख रुपए नकद मिले। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेना की कई हार्ड ड्राइव भी बरामद हुईं। झाओ को इस साजिश से 17 लाख रुपए मिले थे। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा- सैनिकों की सुरक्षा खतरे में डाली अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि झाओ ने सेना में मिली अपनी जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल किया। उसने पैसों के लिए गोपनीय जानकारी चीन से जुड़े लोगों को दी। सेना के काउंटर इंटेलिजेंस कमांड के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल सीन स्टिंचन ने कहा कि झाओ ने सेना की शपथ और अपने साथियों के भरोसे को तोड़ा। उसकी हरकत से सैनिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी।

नेक्सटऐज मीडिया एंड कांलटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए, प्रकाशक, संपादक अनीता यादव द्वारा मुद्रक, रजनी कुमारी मेसेर्स साईं प्रिंटिंग प्रेस डी-85 सेक्टर-06 201301 से मुद्रित कराकर 962 सरफाबाद सेक्टर-73, नोएडा-201304 से प्रकाशित किया,
प्रधान संपादक : रिंकू यादव संपादक : अनीता यादव PRGI No. UPHIN/26/A8255 Ph. : 4403949, Email : unplugindia26@gmail.com